RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

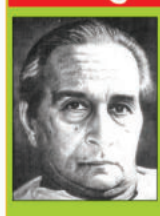

वसंत अपने आप नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। सहज आने वाला तो पतझड़ होता है, वसंत नहीं।

हरिशंकर परसाई

वर्ष-07, अंक - 47 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरूवार 21 अगस्त 2025 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सरकार की नीतियों का विरोध देश विरोध न बनने पाए

माही की गूंज, संजय भटेवरा।

झाबुआ। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि, यहां विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष से ज्यादा तो नहीं लेकिन सत्ता पक्ष से कम भी नहीं है। किसी भी महत्वपूर्ण मसले पर विपक्ष को बराबर महत्व दिया जाता रहा है। यहां तक कि पिछले कई मौकों पर विपक्ष के नेता ने विदेशों में भारत का पक्ष मुस्तैदी के साथ रखा था। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर यह कहते रहे कि लोकतंत्र में सरकारें आएंगी और जाएंगी, कई समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन देश की अस्मिता बरकरार रहना चाहिए।

जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तो पूरे देश सहित समूचा विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा नजर आया, जिसका परिणाम यह रहा कि सरकार ऑपरेशन सिन्दूर अभियान चलाने में कामयाब रही और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। लेकिन सरकार द्वारा अचानक से सीज फायर का फैसला लेना आम जनता के साथ विपक्ष को भी रास नहीं आया। बहरहाल, जो भी परिस्थितियां बनीं, विपक्ष ने सरकार का पूरा साथ दिया और एकजुटता का परिचय दिया।

लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता, जो कि विपक्ष के नेता भी हैं, ने आगामी बिहार चुनाव में चलाए जा रहे मतदाता सूचियों के सघन पुनरीक्षण पर कुछ सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के कुछ तथ्यात्मक आंकड़े पेश किए हैं, जिसके बाद कांग्रेस के नेता सभी जगहों पर इस प्रकार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार के आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं तो चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वह विपक्ष के आरोपों का जवाब दे और उन्हें संतुष्ट करे।

चूंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य कार्य देश भर में विभिन्न चुनाव कराना होता है, लेकिन मुख्य विपक्षी दलों द्वारा इस प्रकार के आरोपों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। वहीं विपक्ष को भी चाहिए कि अगर मतदाता सूचियों या चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है तो वह तत्काल विरोध करे, न कि सांप चले जाने के बाद लाठी ठोके।

इसी प्रकार पूर्व में विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधली का आरोप लगा चुका है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सारी स्थितियों को स्पष्ट किया। मशीनों को हैक किए जाने वाले दावों का परीक्षण भी किया गया, जिसके बाद मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इसी प्रकार चुनाव आयोग कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करे।

वहीं विपक्ष को भी चाहिए कि अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो वह समय रहते इसकी शिकायत करे। बिहार चुनाव को लेकर जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, वहां अगर कुछ गड़बड़ है तो तत्काल स्थानीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। रही बात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश चुनाव की तो अब इसकी शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि समय निकल चुका है। वहीं विपक्ष को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सरकार का विरोध करते-करते देश का विरोध न करने लगे, क्योंकि चुनाव तो हमारा आंतरिक मसला है और उसे हम मिल-बैठकर सुलझा लेंगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रम्प के टैरिफ वार से निपटने के लिए विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और ऐसी कोई भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे मतभेद उजागर हों, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के मतभेद होते हैं न कि मनभेद...।

जनसुनवाई में आए शख्स ने पहले मुख्यमंत्री को कागज थमाए, फिर जड़ दिया थप्पड़

नई दिल्ली, एजेंसी।

बुधवार को साप्ताहिक जनसुनवाई कर रहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक युवक ने हमला कर दिया। यह घटना मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान हुई। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने भी बताया कि जनसुनवाई के बहाने एक शख्स मुख्यमंत्री गुप्ता के पास पहुंचा। उसने पहले मुख्यमंत्री को कुछ कागज दिया, फिर चिल्लाने लगा और थप्पड़ मार दिया। आरोपी को सिविल लाइन थाने ले जाया गया है।

मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों के मुताबिक, जिस समय मुख्यमंत्री जनसुनवाई कर रही थीं, उसी समय एक शख्स अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा। इस दौरान उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया। शख्स को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली मुख्यमंत्री पर हमले करने वाले आरोपी की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है।

दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना की निंदा की है। पार्टी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पर हमले की यह कोशिश जनसुनवाई को पटरी से उतारने की मंशा से की गई है। वहीं पार्टी नेता तेजिंदर बग्गा ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की खबर से हैरान हूं। मैं उनकी सुरक्षा और जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बजरंग बली आप पर कृपा बनाए रखें।

आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली मुख्यमंत्री पर हमले की निंदा की है। पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारी पार्टी का इस तरह के मामलों पर स्पष्ट रुख है।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं की निंदा होनी चाहिए। लेकिन इस घटना ने महिला सुरक्षा की पोल खोल दी है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं तो एक आम महिला राजधानी में कैसे सुरक्षित हो सकती है?

इस घटना पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री पर हुआ हमला निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, एजेंसी।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर बुधवार को देशभर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। संसद परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई सांसद मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद प्रियंका गांधी दिल्ली स्थित वीर भूमि पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सामाजिक मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने पिता राजीव गांधी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को सम्मान मिले, सद्भावना हो और लोकतंत्र व संविधान से देश मजबूती से खड़ा हो। पापा, आपके सपनों को पूरा करना ही मेरा जीवन लक्ष्य है। वहीं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि, आपसे करुणा, प्रेम और देशभक्ति का धर्म मिला। हम दोनों हमेशा इस धर्म का पालन करेंगे। न कोई हमें रोक पाएगा, न कोई हमारे कदम लड़खड़ाएगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजीव गांधी जी ने साहस के साथ परंपरागत रास्तों से हटकर नई सोच और नवाचारी योजनाओं को अपनाया, ताकि भारत इक्कीसवीं सदी के लिए तैयार हो सके। कांग्रेस नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें तकनीकी भारत का शिल्पकार और संचार क्रांति का जनक बताया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा कि, सबसे युवा प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा राजीव गांधी को शत-शत नमन। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि, देश को आधुनिकता और उदारीकरण की ओर ले जाने वाले, सूचना और कंप्यूटर क्रांति के प्रणेता तथा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देने वाले राजीव गांधी जी की जयंती पर कोटिशः नमन।

धोखेबाज पाकिस्तान से संबंध सुधारने का कोई मतलब नहीं - शशि थरूर

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान धोखेबाज है और भारत को उससे संबंध सुधारने के प्रयास नहीं करने चाहिए। एक पुस्तक विमोचन समारोह में थरूर ने कहा कि बार-बार विश्वासघात झेलने के बाद पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में पहला कदम उठाने की भारत में अब कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करके ईमानदारी दिखाने का आग्रह किया।

थरूर ने कहा कि 2012 में आई उनकी पुस्तक में लिखा गया था कि अगर मुंबई जैसा एक और हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत मिले, तो 2008 में हमारी तरफ से दिखाया गया संयम दोबारा दिखाना असंभव होगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों और छुट्टियां मनाने गए मासूमों पर हुए हमले को कोई भी लोकतांत्रिक सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भारत ने हमलों के बाद काफी संयम दिखाया, लेकिन बाद में हुई उकसावे की कार्रवाई के बाद भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा और 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई और फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। एक बार ऐसा कदम उठा लिया जाए तो भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन अब पहला कदम हम नहीं उठाएंगे।

सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए दाखिल किया नामांकन, प्रस्तावक बने प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, एजेंसी। अगले माह 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। बुधवार को राधाकृष्णन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर मौजूद रहे और वे उनके पहले प्रस्तावक बने। निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्रों के चार सेट सौंपे गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता संसद भवन पहुंचे और राधाकृष्णन के साथ खड़े दिखाई दिए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। जनता दल (यूनाइटेड) से ललन सिंह और संजय झा, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी सहित कई नेता उपस्थित रहे। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। वे दो बार कोयंबटूर से सांसद रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से सक्रिय सदस्य रहे हैं। वर्तमान में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रेरणा स्थल में प्रतिष्ठित हस्तियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री और भाजपा नीत गठबंधन के अन्य नेता भी मौजूद थे।

लोकसभा में पेश किए तीन विधेयक, विपक्ष का जोरदार हंगामा, संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाएंगे बिल

नई दिल्ली।

लोकसभा में बुधवार को भारी हंगामा देखने को मिला, जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीन विवादास्पद विधेयक सदन में पेश किए। ये विधेयक प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाने से जुड़े हैं, अगर वे किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिनों तक जेल में रहते हैं। शाह ने जैसे ही ये विधेयक पेश किए, विपक्षी सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने विधेयकों की प्रतियां फाड़कर शाह की ओर फेंकी और नारेबाजी करते हुए सदन के बीच में पहुंच गए।

गृहमंत्री शाह ने स्पष्ट किया कि ये विधेयक जल्दबाजी में नहीं लाए गए हैं और इन्हें संसद की संयुक्त समिति (संयुक्त संसदीय समिति - जेपीसी) को भेजा जाएगा, जिसमें सभी दलों के सांसद सुझाव दे सकेंगे। शाह ने कहा कि हम इतने बेशर्म नहीं हो सकते कि गंभीर आरोपों के बावजूद संवैधानिक पदों पर बने रहें। कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया।

हंगामे के बीच लोकसभा को दोपहर तीन बजे तक स्थगित किया गया। जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो शाह ने कहा कि इन विधेयकों को 31 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाएगा, जो अगले संसद सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते सदन को फिर शाम पांच बजे तक स्थगित करना पड़ा।

ये तीन विधेयक हैं- केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025। इनका मकसद यह है कि अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार कर लगातार तीस दिनों तक जेल में रखा जाता है, तो 31वें दिन वे अपने पद से हटा दिए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ने गिरफ्तारी के बावजूद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था।

एक विधेयक में प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री लगातार तीस दिनों तक किसी ऐसे अपराध के आरोप में हिरासत में रहता है, जिसकी सजा पांच वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, तो राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन हटा देंगे। अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते, तो 31वें दिन के बाद वह व्यक्ति स्वतः मंत्री पद से हटा हुआ माना जाएगा।

विपक्ष ने इन विधेयकों को तानाशाहीपूर्ण और अलोकतांत्रिक बताया और भाजपा पर देश को पुलिस राज्य में बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये विधेयक पूरी तरह से तानाशाही वाले हैं और संविधान के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अगर कल को किसी मुख्यमंत्री पर झूठा मुकदमा दर्ज कर उसे तीस दिन तक जेल में रखा जाए, तो वह अपने आप पद से हट जाएगा। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है।

हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि भाजपा सरकार देश को पुलिस राज्य बनाना चाहती है। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा? हम इन विधेयकों का पूरा विरोध करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सरकार बिना किसी जवाबदेही के सत्ता, पैसा और नियंत्रण चाहती है। उन्होंने भी इन्हें तानाशाही वाला विधेयक बताया।

जीएसटी बैठक : वित्त मंत्री ने राज्यों के मंत्रिसमूह से की चर्चा, कर सुधारों की जरूरत बताई

नई दिल्ली, एजेंसी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों पर राज्यों के मंत्रिसमूह (मंत्रि समूह) के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मंत्रिसमूह को जीएसटी व्यवस्था में व्यापक सुधारों के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। इन सुधारों में कर की दरों में कटौती और कारोबारियों के लिए अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है।

बीमा कराधान और क्षतिपूर्ति उपकर पर गठित मंत्रिसमूह दो दिनों तक केंद्र के 'अगली पीढ़ी' के जीएसटी सुधारों पर विचार-विमर्श करेगा। इसके तहत 5 और 18 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव है। 5 से 7 वस्तुओं पर, जिनमें हानिकारक वस्तुएं भी शामिल हैं, 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू करने का सुझाव दिया गया है।

वर्तमान में जीएसटी 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। खाद्य और आवश्यक वस्तुओं पर शून्य या 5 प्रतिशत की दर से कर लगता है, जबकि विलासिता और अवगुण वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगता है, जिसके ऊपर उपकर भी लगता है।

एक सूत्र के अनुसार वित्त मंत्री ने मंत्रियों के समूह को लगभग 20 मिनट तक संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राज्यों को जीएसटी सुधारों की आवश्यकता के बारे में समझाया।

क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों का समूह ऋण चुकौती अवधि के बाद इसके भविष्य पर निर्णय लेने के लिए गठित किया गया था। इसके अलावा, बीमा पर मंत्रिसमूह स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर की दरें कम करने पर विचार कर रहा था।

दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह को स्लैब और दरों में बदलाव के सुझाव देने और कुछ क्षेत्रों के सामने आने वाली शुल्क-उलटाव की समस्या को दूर करने का काम सौंपा गया था। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह की 21 अगस्त को फिर से बैठक होगी।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अनुसंधान की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे सालाना लगभग 85 हजार करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है। चालू वित्त वर्ष में, अगर नई कर दरें 1 अक्तूबर से लागू होती हैं, तो राजस्व का नुकसान 45 हजार करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

मंत्रिसमूहों की ओर से अनुमोदित होने के बाद, केंद्र के प्रस्ताव को अगले महीने होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। इसमें केंद्र और सभी राज्यों के मंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिवाली तक जीएसटी सुधारों को लागू करने की घोषणा की थी।

एसबीआई अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावी भारित औसत जीएसटी दर शुरुआत में 14.4 प्रतिशत थी, जो सितंबर 2019 में घटकर 11.6 प्रतिशत हो गई। दरों में प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद यह औसत 9.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

शराब ठेकेदार की मनमानी

अपनी मर्जी से दे रहा कमीशन, किसको शराब देना, किसको नहीं देना ये भी तय कर रहा

आबकारी विभाग का मिल रहा पूरा समर्थन, ठेकेदार की शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा माल चालू

माही की गूंज, पेटलावद।

हम कई बार लिख चुके हैं कि क्षेत्र भर में शराब ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है। ठेकेदार के गुर्गे दो पहिया और चार पहिया वाहनों से ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से न केवल शराब की सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि ठेकेदार के अलावा किसी और का माल बेचने वालों पर नज़र भी रखकर पुलिस और आबकारी के माध्यम से शराब को अवैध बता कर पकड़वाया भी जाता है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि शराब ठेकेदार ने केवल शराब दुकान का ठेका लिया है, बल्कि दुकान क्षेत्र के उस ग्रामीण और नगरीय इलाके में भी काउंटर खोलकर शराब बिक्री का ठेका लिया है।

ठेकेदार की मनमानी

शासन को करोड़ों रुपए देकर शराब का ठेका लेने वाले क्षेत्र के शराब ठेकेदार अपनी मनमानी पर उतारू हैं और क्षेत्र में किसको माल (शराब) देना है, किसको नहीं देना, किसको कमीशन देना है, किसको नहीं देना ये तक भी तय कर रहे हैं। जिससे क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेच रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाम न छापने की शर्त पर एक शराब विक्रेता ने बताया कि, ठेकेदार अपनी मर्जी से माल तो देता है लेकिन कमीशन नहीं देता, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। शराब विक्रेता ने ये भी बताया कि, ठेकेदार द्वारा उन्हीं लोगों को माल दिया जा रहा है, जिनको वह देना चाहते हैं, जबकि हम भी शराब

बेचकर रोजगार चाहते हैं। लेकिन ठेकेदार द्वारा हमें शराब नहीं दी जा रही, जबकि जगह-जगह ठेकेदार शराब देकर माल बिकवा रहा है।

ठेकेदार का माल बेचने का दबाव

ठेकेदार द्वारा जो माल दिया जा रहा है, वही माल ग्रामीण क्षेत्रों के काउंटर, ढाबों आदि से बेचने का ठेकेदार का नियम है। जो इस नियम से माल बेचने को राज़ी हैं, वही अवैध शराब बेच सकेंगे। वैसे तो अवैध शराब की धरपकड़ के लिए आबकारी विभाग है, लेकिन अवैध शराब बेचने वालों की सूची ठेकेदार की ओर से उपलब्ध करवा दी जाती है। जिससे आबकारी विभाग को सुविधा हो जाती है और उन अवैध शराब विक्रेताओं पर ही कार्यवाही आबकारी विभाग की ओर से होती है, जिनके नाम ठेकेदार द्वारा आबकारी के स्थानीय अधिकारियों को दिए जाते हैं। आबकारी विभाग ईमानदारी से ठेकेदार का सहयोग कर रहा है।

ठेकेदार का माल नहीं बेचने वालों पर हो कार्यवाही

सरकार को करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले शराब ठेकेदार द्वारा नियमानुसार डायरी धारकों को बेचने के लिए अवैध शराब दी जा रही है। ऐसे में ठेकेदार की शराब नहीं बेचने वालों पर कार्यवाही होना चाहिए। आबकारी विभाग को इस ओर ध्यान देकर ठेकेदार के नियमों को तोड़कर अवैध शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। शराब ठेकेदार द्वारा क्षेत्र भर में कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर नशा मुक्ति अभियान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

सड़क पर गिरे पेड़ से ग्रामीणों को भारी परेशानी

माही की गूंज, बुरहानपुर।

जिले के मंडाभिया खेड़ा और हंदरपुर के बीच सुबह सड़क पर अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया। यह पेड़ किसान हीरामन महाजन के खेत की मेढ़ पर स्थित था। पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई और दोनों गांवों के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

ग्रामीणों ने बताया कि पेड़ गिरने की सूचना तुरंत ही वन विभाग और पंचायत को दे दी गई थी। लेकिन बुधवार शाम तक भी पेड़ को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण ग्रामीणों को आने-जाने में मुश्किल हो रही है। स्थिति यह है कि लोग अपनी बाइक और साइकिल लेकर सड़क पार करने के लिए पेड़ के नीचे से निकालने का जोखिम उठा रहे हैं। कई बार वाहन और लोगों के गिरने की नौबत आ चुकी है। गांव वालों का कहना है कि अगर समय पर पेड़ नहीं हटाया गया तो किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

ग्रामीणों ने वन विभाग और पंचायत पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सूचना देने के बाद भी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ को हटाने के लिए उन्हें खुद ही प्रयास करना पड़ सकता है।

नावरा के रेंजर पुष्पेंद्र जादौन ने इस संबंध में बताया कि उन्होंने बुधवार को ही कर्मचारियों को पेड़ हटाने के निर्देश दिए थे। उनका कहना है कि वे जांच करेंगे कि अब तक पेड़ क्यों नहीं हटाया गया और मौके पर टीम भेजी जाएगी।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पेड़ हटाकर सड़क को आवागमन के लिए सुचारू किया जाए। लोगों का कहना है कि इस सड़क से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं, जिनमें स्कूल जाने वाले बच्चे और कामकाजी लोग भी शामिल हैं। पेड़ हटाने में देरी के कारण न केवल परेशानी बढ़ रही है, बल्कि दुर्घटना का खतरा भी मंडरा रहा है।

पकड़ी गई ड्रग्स फैक्ट्री को लेकर एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन, कुंभकरण बना कार्यकर्ता

माही की गूंज, भोपाल।

राजधानी में उजागर हुई अवैध ड्रग्स फैक्ट्री ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की कार्रवाई में करोड़ों रुपये की मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद हुआ। इस मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने भोपाल में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता कुंभकरण का रूप धारण कर लेट गया और अन्य कार्यकर्ता उसे जगाने की कोशिश करते रहे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की आंखों के सामने नशे का कारोबार फल-फूल रहा है और शासन कुंभकरण की नींद सो रहा है।

595 किलो कच्चा माल भी जब्त

एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सोनी ने कहा कि राजधानी में लंबे समय से यह अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी और युवाओं-छात्रों के बीच नशे का जहर फैला रही थी। डीआरआई ने करीब 92 करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ ही 595 किलो कच्चा माल भी जब्त किया है।

भोपाल नशे की राजधानी बनने की ओर

प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि यह केवल एक फैक्ट्री का मामला नहीं है। पिछले वर्ष अक्टूबर में भी गुजरात से आई 1800 करोड़ रुपये की ड्रग्स भोपाल में पकड़ी गई थी। इसके अलावा तस्करों के बड़े गिरोह का खुलासा भी यहीं से हुआ था। उन्होंने कहा कि भोपाल नशे की राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश सरकार कुंभकरण की तरह सोई हुई है।

बड़े आंदोलन की चेतावनी

भोपाल एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि यह प्रदर्शन मध्यप्रदेश शासन को चेतावनी है। यदि नशे के कारोबारियों और उन्हें संरक्षण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो एनएसयूआई सड़कों पर और भी बड़े आंदोलन करेगी।

पानी नहीं देने पर इंजीनियर ने की पत्नी की हत्या, मां ने दिया साथ

माही की गूंज, सिंगरौली। एलएंडटी कंपनी के इंजीनियर ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद कंबल में शव लपेटकर कार से प्रयागराज ले गया। सबूत मिटाने में मां ने भी उसका साथ दिया। वहां दोनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। घटना 15 अगस्त की है। पुलिस ने आरोपी पति निखिल दुबे और उसकी मां दुरेदश्वरी देवी को प्रयागराज के शास्त्री नगर से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि, आरोपी इंजीनियर की मां दुरेदश्वरी देवी ने शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने में उसकी मदद की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1), 238, 3(5) के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान निखिल ने बताया कि, पानी मांगने पर पत्नी आध्या से कहासुनी हुई थी। गुस्से में पत्नी के सिर को किचन के प्लेटफॉर्म पर पटक कर उसकी हत्या कर दी।

विंध्यनगर टीआई अर्चना द्विवेदी के मुताबिक, 15 अगस्त को फतेहपुर से सुनील दुबे ने फोन पर सूचना दी कि, उनके दामाद निखिल दुबे ने उन्हें अपनी बेटी की मौत की जानकारी दी है। जब मायके वालों ने इलाहाबाद (प्रयागराज) जाकर पता किया तो घर में ताला लगा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को विंध्यनगर में निखिल के आवास की जांच करने के लिए कहा। पुलिस ने निखिल के आवास का ताला तोड़कर जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला।

बेकाबू बस का कहर : बाइक, कार और रिक्शा को मारी टक्कर, दो की मौत, दो घायल

माही की गूंज, इंदौर।

शहर में मंगलवार शाम बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार एक बेकाबू कॉलेज बस ने पहले बाइक, फिर कार और रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर एकांश पंड्या और छात्रा मानसी श्रीवास की मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्रा और रिक्शा चालक घायल हो गए।

तेज रफ्तार बनी मौत की वजह

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा अंतिम चौराहे पर हुआ। मेडिकैप्स विश्वविद्यालय की बस बड़ा गणपति से राजमोहल्ला की ओर जा रही थी। इसी दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया। बस ने सबसे पहले बाइक सवार एकांश को कुचला, उसके बाद पैदल जा रही दो छात्राएं चपेट में आ गईं। मानसी की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई।

हड़बड़ाहट में चालक ने बस नहीं रोकी और आगे कार व रिक्शा को भी टक्कर मार दी। इसमें रिक्शा चालक को चोटें आईं।

मृतक दवाई लेने निकला था

जानकारी के मुताबिक मृतक एकांश पंड्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और हादसे के वक्त वह अपनी मां के लिए दवाई लेने निकला था। मानसी श्रीवास हुकुमचंद कॉलोनी में रहती थी। घायल छात्रा का इलाज कपड़ा मार्केट अस्पताल में जारी है।

लोगों ने पकड़ा चालक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस चालक को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को गिरफ्तार कर लिया और बस को जब्त कर थाने भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर भारी ट्रैफिक रहता है, इसके बावजूद चालक लापरवाही से तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था।

सपा में काफी पुराना है महिला अपमान का सिलसिला

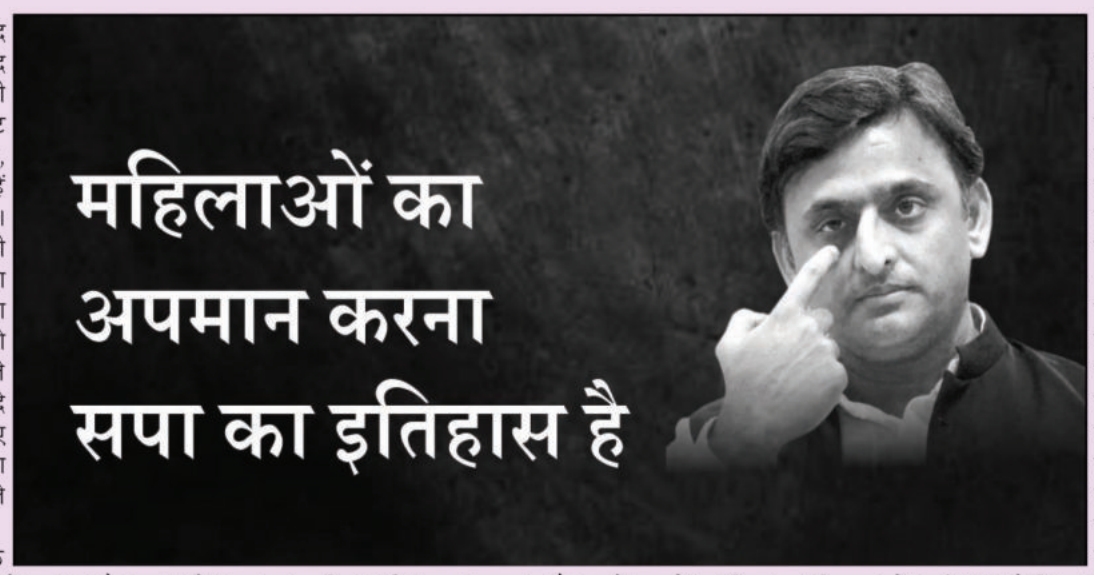

समाजवादी पार्टी (सपा), जिसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताजी मुलायम सिंह यादव की तूती बोलती थी। लेकिन समय-समय पर इस पार्टी पर महिलाओं का सम्मान न करने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। यह सिलसिला मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक जारी है। महिलाओं का अपमान करने के तमाम आरोप न केवल पार्टी नेताओं के बयानों से उपजे हैं, बल्कि उनके कार्यों और नीतियों से भी जुड़े हैं। विपक्षी दल, खासकर भाजपा इन मुद्दों को उठाकर एसपी को महिला विरोधी करार देती रही है। समाजवादी पार्टी पर महिलाओं के अपमान के तमाम ऐसे आरोप लगे, जो समय-समय पर पार्टी की छवि को धूमिल करते रहे।

सबसे चर्चित उदाहरण 2014 का है, जब मुलायम सिंह यादव ने मोरादाबाद में एक रैली के दौरान बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा पर सवाल उठाते हुए कहा था, लड़के हैं, गलती हो जाती है। इस बयान ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। मीडिया और महिला अधिकार संगठनों ने इसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशील बताया, क्योंकि यह बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को गलती मानकर हल्का कर रहा था। मुलायम के इस बयान की वजह से सपा पर आरोप लगा कि पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे प्रो-रेपिस्ट रुख बताया, जिससे पार्टी की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा।

महिलाओं के अपमान को लेकर सपा के एक और प्रमुख नेता आजम खान भी विवादों में घिरे रहे हैं। 2019 में रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान, आजम ने भाजपा उम्मीदवार जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने खाकी अंडरवियर का जिक्र किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे अत्यंत अपमानजनक बताते हुए नोटिस जारी किया। इससे पहले, संसद में भाजपा सांसद रमा देवी पर भी आजम ने सेक्सिस्ट कमेंट किया, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इन बयानों ने एसपी पर आरोप लगाया कि पार्टी के नेता महिलाओं को सम्मान नहीं देते और चुनावी फायदे के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

2017 के विधानसभा चुनावों में सपा पर और बड़ा आरोप लगा जब कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति पर बलात्कार का केस दर्ज हुआ। एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी ने प्रजापति पर गैंगरेप का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एसपी पर आरोप था कि पार्टी ने आरोपी को संरक्षण दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एसपी को बलात्कारियों का संरक्षक कहा, और महिलाओं की असुरक्षा का मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बना। हाल के वर्षों में भी ऐसे आरोप जारी हैं। 2024 में अयोध्या बलात्कार कांड में एसपी नेता मोइन खान पर 12 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी को महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया, और पुराने बयानों का जिक्र किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि एसपी अपराधियों को बचाती है, जबकि एसपी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। ये घटनाएं सपा की छवि को काफी प्रभावित करती रही हैं। परिणाम यह हुआ कि पार्टी ने जब महिलाओं के लिए योजनाएं चलाईं, जैसे स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, लेकिन आरोपों ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। जब महिलाओं का सम्मान राजनीति का मूल होना चाहिए, तब ऐसे विवादों से समाज में असमानता बढ़ती है। सपा को इन आरोपों से सीख लेकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, वरना राजनीतिक नुकसान जारी रहेगा।

बात आज के माहौल की कि जाये तो 2027 में जबकि सपा उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं तब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की लगातार बनती महिला विरोधी छवि ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सोचने को मजबूर कर दिया है कि वह महिला स्वाभिमान के प्रति ज्यादा लचीला रूख अख्तियार करें। वर्ना 2027 के विधान सभा चुनाव में उनको महिला वोटरों से बड़ा झटका मिल सकता है। मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में जिस तरह से अखिलेश अपनी ही पार्टी की महिला नेताओं का न केवल अपमान बर्दास्त करते जा रहे हैं बल्कि विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल कर आखिलेश ने यह भी साबित कर दिया है कि उनको यह भी अच्छा नहीं लगता है कि उनकी विधायक पूजा पाल जिसके विधायक पति राजू पाल की माफिया अतीक अहमद ने हत्या करा दी थी,वह अतीक के खिलाफ मुंह खोलें। उनको जिस महिला का सुहाग उजाड़ दिया गया उसका दर्द समझने की बजाये इस बात की चिंता हो रही है कि अतीक के खिलाफ पूजा पाल के विधान सभा के अंदर दिये गये बयान से मुस्लिम वोटर नाराज नहीं हो जायें,इस लिये बिना किसी कारण बताओ नोटिस दिये पूजा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे पूर्व अखिलेश ने अपनी सांसद पत्नी डिंपल यादव के अपमान पर भी अपना मुंह उस समय बंद रखा था जब डिंपल को एक मौलाना रशीदी ने नंगी कहकर संबोधित किया था।

अजय कुमार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का मुद्दा तब गरमाया जब सपा ने विधायक पूजा पाल को सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के चलते उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है. इस एक्शन को सपा नेता सही बता रहे हैं, तो बीजेपी ने अखिलेश को घेरना शुरू कर दिया है. बीजेपी इस प्रकरण को महिला-सुरक्षा और न्याय हुआ के रूप में पेश कर रही है.कुल मिलाकर पूजा पाल के रूप में बीजेपी को एक नया ब्रांड एंबेसडर और सपा के पीडीए का काउंटर प्लान मिल गया है.राजू पाल की हत्या के बाद सहानुभूति की जो लहर पूजा पाल के साथ बसपा से सपा की ओर शिफ्ट हुई थी, अब उसका सियासी लाभ बीजेपी भी उठाने की तैयारी में है. बीजेपी, सपा को ओबीसी विरोधी बताने में जुटी है. बीजेपी की रणनीति पूजा पाल के बहाने अखिलेश के सबसे बड़े विनिंग फॉर्मूले पीडीए की हवा निकालने की है. यूपी में पाल-बघेल जाति की पिछड़ों में अच्छी-खासी संख्या है, जो सपा के पीडीए की सियासी रीढ़ मानी जाती है. इस तरह बीजेपी अखिलेश यादव को पाल समाज का विरोधी बताने की कवायद करने में जुटी है।

लापरवाह शिक्षक : ग्रामीण अंचलों में समय पर नहीं खुल रही स्कूल, कीचड़ में खेलते बच्चे

मॉनिटरिंग करने वाले जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही देख-रेख कर रहे हैं

माही की गूंज खवासा। सुनील सोलंकी

ग्रामीण अंचलों में किस तरह से शिक्षा के हाल बेहाल हो रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। मॉनिटरिंग करने वाले जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही देख-रेख कर रहे हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवता व महत्व बताते हुए सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ ही सरकारी स्कूलों में निशुल्क गणवेश, मध्यान भोजन आदि की सुविधा शासन ने कर रखी है। ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चे अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचे। लेकिन ग्रामीण अंचलों में शिक्षक ही लापरवाह बने हुए हैं। जिसके कारण बच्चों का भविष्य दाव पर लगा हुआ है।

ऐसा ही मामला माही की गूंज के सामने आया जो बेडावा संकुल के अंतर्गत कड़ीकुआं प्राथमिक स्कूल में दो शिक्षक पदस्थ है। दोनों ही शिक्षक 10:30 से 11 बजे के मध्य स्कूल उपस्थित नहीं थे। बच्चे स्कूल के बाहर कीचड़ नुमा परिसर में खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

ग्रामीणों से पूछा तो कहा कि, सर जिस दिन भी आते है तो वह 11 बजे बाद ही आते हैं।

बच्चों का कहना है कि ,शिक्षक हमेशा लेट आते हैं और इसी तरह से स्कूल प्रतिदिन संचालित होता है। ग्रामीणों के अनुसार एक शिक्षक बाजना से आते हैं तो एक थांदला के पास किसी गांव से आते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि, यहां सर हमेशा लेट ही आते हैं। बच्चे इसी तरह से स्कूल के पास खेलते हैं। बारिश होने के कारण कीचड़ में बच्चे खेलते है । कड़ीकुआं में मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था भी नहीं है कि कभी किसी को शिकायत कर सके ।आधा किलोमीटर दूर जाने के बाद ही मोबाइल में नेटवर्क आता है। यह भी हमारे लिए सबसे बड़ी वीडबना है। ग्रामीणों ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि, अक्सर शिक्षक इसी तरह से लेट आते हैं यहां कभी भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौका मुआयना नहीं किया है। तो वही स्कूल में रंगाई- पुताई भी नहीं की गई है।आसपास गंदगी भी स्कूलों में दिखाई दे रही है। वही जन शिक्षक की भी लापरवाही इसमें सामने नजर आ रही है। जिनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी है वह भी लापरवाह बने हुए हैं। अगर इसी तरह से ग्रामीण अंचलों में जवाबदार अधिकारी व शिक्षक लापरवाह बनेंगे तो किस तरह से काम चलेगा। क्योंकि यह नन्हे बच्चे ही देश का भविष्य है और इनको पड़ाने की जिम्मेदारी इन शिक्षकों के ऊपर है। मगर जिम्मेदार शिक्षक ही लापरवाह बनें रहेंगे तो देश के भविष्य का क्या होगा? एक ग्रामीण ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि, सर प्रतिदिन लेट आते हैं, दोनों सर में कभी एक आते हैं तो कभी दूसरा थोड़ी देर बाद आता है। इस तरह से स्कूल संचालित होता है। एक शिक्षक बाजना से आते हैं। उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई इसलिए वह दो दिन से नहीं आ रहे हैं। और एक शिक्षक है जो मीटिंग में गए हैं यह कहकर ग्रामीणों को अवगत करवाया ओर नही आए। अब इस तरह से अगर शिक्षक ग्रामीण अंचलों में स्कूलों में समय पर नहीं पहुंचेंगे तो किस तरह से शिक्षा का उद्धार हो पायेगा इससे सहज ही अंदाज़ लगाया जा सकता है।

– समय पर पहुचे बच्चे पर शिक्षक के स्कूल नही आने पर बच्चे बाहर कीचड़ में खेलते हुए।

वही मामले में प्राथमिक स्कूल कड़ीकुआं के प्रभारी शिक्षक कड़वा भूरिया से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मैं, बेड़ावा संकुल में मीटिंग में आया हुआ हूं। वहां एक और शिक्षक पदस्थ है। वह थोड़ी देर में आ जाएंगे यह कहकर उन्होंने आगे कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और फोन काट दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अलीराजपुर को कांस्य पदक से किया सम्मानित

माही की गूंज, अलीराजपुर। केंद्र एवं राज्य शासन के तहत गत तीन माह से प्रदेश के आकांक्षी जनपदों में संपूर्णता अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान में महिलाओं के स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण, पोषण, आहार तथा कृषि आधारित कारकों को प्राथमिकता दी गई।

अलीराजपुर जिले ने इस अभियान में उल्लेखनीय कार्य करते हुए कट्ठीवाड़ा जनपद को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर कॉपर मेडल, स्मृति चिन्ह एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ। भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिला अलीराजपुर को कांस्य पदक प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर सिंह के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी।

बाजार में भाव नहीं, फेंकनी पड़ी रही सब्जियां

माही की गूंज, आम्बुआ। इन दिनों वर्षा ऋतु में ग्रामीण कृषक खेतों में मुख्य फसलों के साथ मौसमी सब्जियां भी उगाते हैं और इन्हें दैनिक खर्च तथा रोज़मर्रा की जरूरत के लिए बाजार में बेचने लाते हैं। लेकिन क्षेत्र में अधिक उपज होने के कारण बाजार में लागत के हिसाब से मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

इन दिनों गिलकी, तोरई, बैंगन, हरी मिर्च, लौकी और करेला जैसी सब्जियों की भरमार है। किसान इन्हें औने-पौने दामों पर बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बिकती नहीं हैं तो ग्रामीण कृषक मजबूरी में इन्हें इधर-उधर फेंक देते हैं। उनका कहना है कि इतना भार सिर पर उठाकर वापस ले जाना संभव नहीं होता। स्थिति यह है कि अब तो जानवर भी इन सब्जियों को नहीं खा रहे हैं। फलस्वरूप सब्जी बाजार क्षेत्र में गंदगी फैल जाती है, जिसे बाद में सफाईकर्मी उठाकर फेंकते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस समस्या का समाधान निकालने की मांग की है।

समिति कानाकाकड़ की टीम को सम्मानित किया गया

माही की गूंज, अलीराजपुर।

भारत शासन की सहकार से समृद्धि योजना अंतर्गत झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में बी-पेक्स कानाकाकड़ को प्रथम ई-पेक्स घोषित किया गया। इस उपलब्धि पर संस्था प्रबंधक तेजबहादुर सिंह, प्रशासक श्रीमती सोनू भूरिया एवं ऑपरेटर राज राठौड़ को 15 अगस्त 2025 को आयोजित गरिमामय जिला स्तरीय कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं 5 हजार की नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया।

संस्था की इस उपलब्धि पर उपायुक्त सहकारिता जी.एल. सोलंकी, बैंक नोडल एवं मास्टर ट्रेनर राजेश राठौड़, अतिशय प्रतिनिधि प्रवीण बघेल तथा शाखा प्रबंधक, उदयगढ़ जगदीश चौहान ने टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

बाबा महाकाल की राजसी सवारी में बड़ा हादसा टला

माही की गूंज, उज्जैन।

विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकाल की अंतिम और राजसी सवारी 18 अगस्त को निकली गई। इस सवारी में लाखों की संख्या में भक्त बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे, लेकिन इस दौरान एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई।

सवारी मार्ग से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें जर्जर मकान का छज्जा गिरते हुए साफ देखा जा सकता है जो उज्जैन के ढाबा रोड का है यह छज्जा डॉक्टर की क्लिक के ऊपर का है।

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि दो युवक सवारी मार्ग पर स्थित एक पुराने मकान की छत पर चढ़कर बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन कर रहे थे। तभी अचानक मकान का छज्जा भरभराकर गिर गया। युवक दीवार से लटकता नजर आया और वह बाल-बाल बच गया। गनीमत रही कि छज्जे के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा नहीं था अन्यथा यह हादसा बड़ा रूप ले सकता था। नगर निगम के दावों पर उठे सवाल इस घटना ने उज्जैन नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। निगम ने पहले दावा किया था कि महाकाल की सवारी से पहले पूरे मार्ग का निरीक्षण किया गया और जितने भी जर्जर मकान थे, उन्हें चिन्हित कर गिरा दिया गया है। लेकिन यह वीडियो साफ कर रहा है कि निगम की कार्यवाही अधूरी और सिर्फ कागज़ों तक सीमित रही।

फसल बीमा की सूची ना मिलने और सर्वे में विसंगति से भड़के किसान

बीएसएनएल टावर पहुंचा किसानों का विरोध, घंटों धरने पर बैठे रहे, बात नहीं सुनी तो टावर पर चढ़े

माही की गूंज, पेटलावद।

सोमवार को पेटलावद विकासखंड की एक दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के किसानों ने फसल बीमा के विसंगतिपूर्ण सर्वे और दावा राशि के प्रति रोष व्यक्त करते हुए विरोध किया। विरोध समय पर उग्र हो गया जब उनकी बातें तहसील में घंटों तक धरना देने के बाद भी नहीं सुनी गईं। किसानों को अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाने के लिए टावर पर चढ़ना पड़ा।

हालांकि जैसे ही किसानों के टावर पर चढ़ने की सूचना पुलिस और राजस्व अधिकारियों के पास पहुँची, आनन-फानन में बड़ी संख्या में पुलिस बल बीएसएनएल कार्यालय पहुँचा और नाराज किसानों को टावर पर चढ़ने से रोका गया। इस दौरान कुछ किसान टावर पर कुछ दूरी तक चढ़ गए थे जिन्हें समझाइश और आश्वासन देकर नीचे उतारा गया।

दरअसल, विकासखंड के ग्राम बरवेट, बावड़ी, जामली, उन्नई, कोदली सहित कई गाँवों के किसानों का मानना है कि, फसल बीमा करने वाली कंपनी ने जो सर्वे किया वह विसंगतिपूर्ण है क्योंकि कुछ किसानों को बीमे की अच्छी राशि मिली तो कुछ किसानों को बहुत कम राशि मिली। इसी को लेकर किसानों का विरोध था। किसानों ने तहसील कार्यालय में करीब 4 घंटे तक बैठकर अपनी बात प्रशासन के सामने रखने की कोशिश की किंतु इस दौरान किसानों को प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला। किसानों के विरोध को देखते हुए स्थानीय कृषि विभाग के कर्मचारी और उप संचालक कृषि नगीन रावत झाबुआ से पेटलावद पहुँचे। किसान रावत से फसल बीमा में जिन किसानों के क्लेम स्वीकृत हुए हैं, उसकी सूची माँगने लगे। रावत ने किसानों को बताया कि, अभी ऐसी सूची प्राप्त नहीं हुई है जिस पर किसान भड़क गए। कई किसानों ने अपने पड़ोसी किसानों को ज्यादा राशि का क्लेम मिलने और स्वयं को कम मिलने की बात भी बताई। इस दौरान हंगामा हुआ तो कृषि अधिकारी वहाँ से थोड़ी देर में ही चले गए।

टावर पर चढ़ने लगे किसान

किसानों को लगा कि उनकी बात ना तो प्रशासन सुन रहा है और ना ही कृषि विभाग, तो बड़ी संख्या में किसानों ने रूपगढ़ रोड स्थित बीएसएनएल कार्यालय का रुख किया। किसान टावर पर चढ़कर अपना विरोध जताना चाहते थे किंतु इसकी सूचना पुलिस तक पहुँच गई, जिसके चलते मौके पर बड़ी संख्या में बल तैनात हो गया और किसानों को टावर पर चढ़ने से रोका गया। इस दौरान कुछ लोग टावर के आधे हिस्से तक चढ़ने में सफल हो गए, जिन्हें नायब तहसीलदार अंकिता भिंडे और थाना प्रभारी निर्भय सिंह ने समझाइश देकर नीचे उतारा।

इससे पूर्व जिला कृषि विभाग अधिकारी नगीन रावत किसानों को समझाइश देने पहुँचे लेकिन किसानों के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाए और उल्टे पैर लौट गए, जिसके बाद किसानों का सब्र टूट गया और वे टावर पर चढ़ने पहुँच गए।

फोन पर मिला आश्वासन

पूरे दिन चले किसानों के विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए एक बार भी एसडीएम ने किसानों से मिलकर उनकी समस्या सुनने की जहमत नहीं उठाई। जब मामला जिला अधिकारियों तक पहुँचा तो एसडीएम ने मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार के फोन से किसानों से बात की और उन्हें 15 से 20 दिनों में फसल बीमे की सूची उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। तब जाकर किसानों ने अपना विरोध खत्म किया।

हैरानी तो इस बात की है कि यदि यही बात एसडीएम किसानों को सुबह विरोध के समय कह देती तो किसानों का विरोध वहीं समाप्त हो जाता। खैर, इन दिनों जिले में पेटलावद एसडीएम की कार्यप्रणाली की खूब चर्चा है। सूत्रों की मानें तो एसडीएम के रवैये की शिकायत पेटलावद के कई भाजपाई प्रभारी मंत्री से लेकर जिले में निवासरत महिला एवं बाल विकास मंत्री से कर चुके हैं, पर एसडीएम के व्यवहार में कोई नरमी ना तो आम लोगों और ना ही जनप्रतिनिधियों को दिख रही है।

किसान नेता जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि, फसल बीमा में कई किसानों के नाम छूटे हैं जिन्हें क्लेम नहीं मिला है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनका बहुत अधिक क्लेम स्वीकृत किया गया है। हमने कृषि विभाग से पूरी सूची माँगी है। घंटों तक तहसील में बैठने के बाद भी प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला तो टावर पर चढ़ने का निर्णय लिया, जिसके बाद अफसरों ने हमारी बात सुनी। 20 दिन का आश्वासन मिला है। इस दौरान पूरी सूची और फसल बीमा कंपनी से किसानों की बैठक की बात हुई है।

नगीन रावत (उप संचालक कृषि, झाबुआ) ने बताया कि, जिले में पेटलावद विकासखंड के किसानों को सर्वाधिक क्लेम 19 करोड़ 30 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है जो रिकॉर्ड है। क्लेम की पूरी सूची बीमा कंपनी से प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही प्राप्त होगी किसानों को प्रदान कर दी जाएगी।

वादा खिलाफी नहीं चलेगी

भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र हामड़ ने बताया कि, स्थानीय प्रशासन द्वारा वादा खिलाफी कर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों को 13 अगस्त को मिलने का आश्वासन एसडीएम ने दिया और बाद में अन्य अधिकारियों ने बात को सोमवार तक टाल दिया। जब किसान सोमवार को पहुँचे तो उनसे मिलने कोई नहीं आया। पाँच घंटे के धरने के बाद भी प्रशासन नहीं जागा तो किसान भड़क गए। किसान केवल सरकारी रिकॉर्ड और आँकड़े चाहते हैं जो नहीं दिए जा रहे हैं। हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा अगर प्रशासन हमें संतोषजनक जवाब नहीं देता।

संपादकीय

जेल सुधार में हरियाणा की बदलावकारी पहल

इसमें दो राय नहीं कि जब भी मूल रूप से जेल की अवधारणा का विकास हुआ होगा, तो उसका मकसद भटके लोगों के जीवन में सुधार ही रहा होगा। किसी सभ्य समाज के कायदे-कानून तोड़ने वाले, भटके हुए लोगों को जेल के एकाकी जीवन में आत्ममंथन का समय देने का भी मकसद रहा होगा। साथ ही यह भी अहसास कराना होगा कि समाज से विलग रहने के क्या मायने हैं। वहीं दूसरी ओर जीवन मूल्यों व सामाजिकता का अहसास कराना भी मकसद रहा होगा। दरअसल, भारतीय न्याय संहिता, 2023 पर आधारित नई व्यवस्था छोटे अपराधों के लिए दोषियों को जेल भेजने के बजाय समाज सेवा करने का अवसर देती है। ताकि उन्हें अपनी गलती का अहसास हो और उत्तरदायित्व के साथ सामाजिकता का बोध हो सके। हरियाणा सरकार द्वारा जारी सामुदायिक सेवा दिशानिर्देश, 2025 की अधिसूचना आपराधिक न्यायिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। जिसका लक्ष्य दंड देने के बजाय सुधार व बदलाव है। ऐसे समय में जब देश की जेलें कैदियों की निर्धारित संख्या से कहीं अधिक बोझ उठा रही हैं। विचाराधीन कैदियों की संख्या 76 फीसदी से अधिक है, राज्य की यह पहल कम जोखिम वाले अपराधियों के लिये कारावास का सकारात्मक विकल्प प्रदान करती है। निस्संदेह, इस पहल का दायरा व्यापक होने के साथ ही उद्देश्यपूर्ण भी है। यह व्यवस्था कम संगीन अपराधों के लिये दोषियों को पार्कों के रखरखाव, अस्पतालों में मरीजों की सहायता करने, आंगनबाड़ियों में योगदान देने, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, स्वच्छ भारत तथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे राष्ट्रीय अभियानों में योगदान के लिये प्रेरित करती है। इस बाबत जारी दिशा-निर्देश किशोरों के लिये भी भूमिकाएं निर्धारित करते हैं। मसलन, नेशनल कैडिट कोर प्रशिक्षण, राष्ट्रीय सेवा योजना, पर्यावरण परियोजनाएं तथा महिलाओं के लिये प्रसूति वार्ड व शिशु देखभाल केंद्र जैसे सुरक्षित स्थानों पर सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। निश्चय ही नई व्यवस्था जहां एक ओर अपराधियों को उनके अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करती है, वहीं समाज में उनके योगदान को बढ़ावा देती है।

दरअसल, हरियाणा मॉडल के तहत की जाने वाली पहल, उसे अन्य राज्यों के प्रयासों से विशिष्टता प्रदान करती है। जैसे कि दिल्ली में 40 से 240 घंटे की सेवा निर्धारित करने वाली नीति से अलग, इसके परिचालन का विवरण, इसे विश्वसनीय बनाता है। इसके अंतर्गत बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैग की गई तस्वीरें, वीडियो प्रमाण और प्रगति रिपोर्टिंग सत्यापन इसकी सार्थकता सुनिश्चित करती है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को गौशालाओं और वृद्धाश्रमों में सेवा करने की सजा और जम्मू की एक अदालत द्वारा अपराधियों को स्वास्थ्य केंद्र और पार्क की सफाई करने के लिये बाध्य करने का आदेश यह दर्शाता है कि सामुदायिक सेवा समाज को लाभ पहुंचाने के साथ ही भटके व्यक्ति के व्यवहार को कैसे नया रूप दे सकती है। निस्संदेह, इस सुधार अभियान को सफल बनाने के लिये सुरक्षा उपाय भी बेहद जरूरी हैं। इस बात में सावधानी बरती जानी चाहिए कि समाज में बार-बार अपराध करने वालों को इस व्यवस्था से बाहर रखा जाए। दूसरा, इससे जुड़ी निगरानी पारदर्शी और मजबूत होनी चाहिए। जिसमें सावधानी से निगरानी और चूक करने पर त्वरित दंड की व्यवस्था भी शामिल है। दूसरा उनके कार्य के परिणाम का मूल्यांकन होना चाहिए कि अभियुक्त अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। इस बात का भी मूल्यांकन होना चाहिए क्या पीड़ितों को इस तरह की सजा दिए जाने से राहत मिली है। यह भी कि क्या समाज में अपराध की पुनरावृत्ति कम हुई है। यह इस व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष है कि छोटी-मोटी गलतियों को यह सामाजिक ऋण चुकाने के अवसर में बदल देता है। साथ ही कारावास से होने वाले नुकसान को कम करता है। कई बार जेल के हालात, विषम परिस्थितियों में भूलवश अपराध करने वाले व्यक्ति को पेशेवर अपराधी बना देते हैं। नई पहल से अपराधी में नागरिक उत्तरदायित्व बोध का भी विकास होता है। यदि इस अभियान को विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जाता है तथा ऐसे लोगों की सतर्क निगरानी की जाती है तो यह राष्ट्र के लिये सुधारात्मक न्याय का एक मॉडल भी बन सकता है।

परमाणु अस्त्रों को लेकर गैर जिम्मेदार बयानबाजी

परमाणु युग की सदा अपनी एक अलग भाषा रही है। शीत युद्ध के निवारक (डिटेरेंट) और पारस्परिक विनाश सुनिश्चित करने वाले इंतजाम से आगे चलकर, इसको 'विश्वसनीय न्यूनतम निवारक' और 'उपयोग में पहल नहीं' जैसे सौम्य नाम देने तक, हर वाक्यांश सावधानी से गढ़ा जाता था। व्याकरण अपने आप में संयम का एक औजार बन गया। धारणा ये रही कि इस परमाणु-व्याकरण से अंकुश बनता है और यह उनका उपयोग रोककर रखता है।

परस्पर विरोधियों तक में भी समझ थी कि परमाणु मामलों में, शब्दों में वेग होता है- वह जो सैन्य लामबंदी, डराने या एक भी मिसाइल हिलाए-डुलाए बिना तनाव अथवा टकराव में बढ़ोतरी करने में सक्षम होता है। सार्वजनिक संवाद निवारण के अभिन्न अंग थे; बयान स्पष्टता भरे और नपे-तुले शब्दों में गढ़कर जारी किए जाते क्योंकि कोई एक गैर-जिम्मेदार वाक्यांश सैन्य गतिविधि या बेबात का अलर्ट पैदा कर सकता था। अब वह अनुशासन कमज़ोर पड़ता जा रहा है। संयम का व्याकरण स्थूल बन गया है। जहां कभी परमाणु ताकत का जिक्र इरादतन संदेशों तक सीमित था, अब वह चुनावी रैलियों, प्रेस वार्ताओं और टेलीविज़न भाषणों में आन घुसा है। परमाणु संदर्भ में इस किस्म की नाटकीय जुमलेबाजी हानि रहित नहीं होती; यह उन्हीं नियमों का उल्लंघन करने जैसा है जिन्होंने दशकों तक दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाए रखा है।

चुप्पी की ताकत प्रबल करना- खतरा न केवल उससे है जो कुछ कहा जाता है बल्कि जो अनुत्तरित रह गया, उससे भी है। जब एक मेज़बान देश की चुप्पी संयुक्त राष्ट्र की अनुपस्थिति और अन्य परमाणु ताकतों की उदासीनता मिलकर, किसी परमाणु धमकी को बिना ऐतराज जाने दे,तो वे जवाबदेही दरकिनार और परमाणु मानक कमजोर कर देते हैं।

विरोधाभास पर टिका परमाणु निवारक- हथियार पास होना युद्ध रोकने के लिए है न कि युद्ध छेड़ने को। यह विरोधाभास केवल संयम, रुख, सैन्य तैनाती और इनसे बढ़कर, भाषा के जरिये जीवित रहता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रणनीतिकार थॉमस शेलिंग ने चेताया था कि निवारण केवल हथियारों तक सीमित नहीं, 'जोखिम के हेरफेर' से भी जुड़ा है। इसलिए, भाषा शस्त्रागार का एक हिस्सा है। गैर-जिम्मेवार तैनाती की तरह, लापरवाह शब्द भी संतुलन खतरनाक रूप से बिगाड़ सकते हैं।

हमारे पूर्व नौसेना प्रमुख, एडमिरल अरुण प्रकाश ने चेताया है कि परमाणु शब्दावली भी परमाणु रुख जितनी ही जोखिम भरी है। उनका कहना है कि लंबे समय तक भारत की विश्वसनीयता का आधार दोनों ही मामलों में अनुशासित संयम बनाए रखना रहा। परमाणु युग में लापरवाह बयानबाजी को महज घरेलू राजनीति वाली जुमलेबाजी मानकर खारिज करना खतरनाक व गलत आकलन हो सकता है।

बंकर से नहीं, खुलेआम- एक स्पष्ट मामला इस गिरावट को दर्शाता है। एक अग्रणी लोकतंत्र की भूमि पर, एक परमाणु-शस्त्र सपंन्न मुल्क का सेनाध्यक्ष ऐलान करता है-'अगर हमने पाया कि हम डूबने जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे'। यह बात उन्होंने किसी बंकर में फुसफुसाकर नहीं कही, बल्कि घरेलू और वैश्विक श्रोताओं के सामने सरेआम माइक्रोफोन में बोली। मेजबान देश ने इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया। संयुक्त राष्ट्र ने चुप्पी साध ली। सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्यों ने आंखें फेर लीं। यह संकेत देता है कि कूटनीतिक कीमत चुकाए बिना परमाणु ब्लैकमेल की जा सकती है। बिन ऐतराज प्रत्येक धमकी अगले धमकी की सीमा को और छोटी कर देती है, और संयम को उद्दंडता में बदल देता है।

संधियों से परे- इस ख़तरे का फैलाव परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) जैसी संधियों से भी कहीं आगे तक जाता है। असली ख़तरा सिर्फ़ इसमें नहीं कि परमाणु अस्त्रों का नियंत्रण किसके पास है बल्कि इसमें भी है कि परमाणु हथियारों को लेकर बात कैसे की जाती है, कैसे उपयोग की धमकी जाती है और कैसे इस सबका सामान्यीकरण किया जा रहा है। जब एक पराजित सेनाध्यक्ष, अपने ही प्रधानमंत्री को पीछे करके, किसी दूसरे लोकतंत्र की धरती से अपने लोकतांत्रिक पड़ोसी और आधी दुनिया को धमकी दे डाले, और संसार चुप्पी साध ले, तो यह हरकत किसी संधि के उल्लंघन से ज़्यादा विनाशकारी मिसाल कायम करने वाली है। यह दुनिया भर के सत्ताधीशों को संदेश देता है कि परमाणु ब्लैकमेल का उपयोग, निर्भय होकर खुलेआम किया जा सकता है। यह बर्ताव संयम के मूल व्याकरण को बेमाने करता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ऐसी बयानबाज़ी का इस्तेमाल केवल घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए है। लेकिन परमाणु युग में धारणा भी क्षमता जितनी ही खतरनाक हो सकती है। एक गलत जुमला प्रतिद्वंद्वी को निवारक रुख अपनाने को प्रेरित कर सकता है। एक अस्पष्ट वाक्यांश,नीयत को लेकर ग़लतफ़हमी पैदा कर सकता है। और जब विवादित सीमाओं से लेकर साइबर हमले की घटनाओं तक, संकट पहले से ही एक साथ चले हुए हों दृ गलती करके बच जाने की गुंजाइश खतरनाक रूप से काफी कम रह जाती है।

अन्य मानदंडों से सबक- विगत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दर्शा चुका है कि संयम न केवल शस्त्रागार के जरिए, बल्कि सैद्धांतिक रूप में संहिताबद्ध करके भी हासिल किया जा सकता है। साल 1997 की ओटावा बारुदी सुरंग संधि ने साबित कर दिया था कि जब दुनिया एकमत हो जाए कि कुछ हथियार एकदम अस्वीकार्य हैं, तो अवहेलना का कलंक काफी अहमियत रखता है। रासायनिक हथियार सम्मेलन ने भी यह स्थापित किया कि परिस्थिति जैसी भी हो, कुछ ख़तरे वैश्विक रूप से रेड लाइन पार कर जाते हैं। यहां तक कि अनिच्छुक शक्तियों को भी खुले तौर पर नियमों की अवहेलना करने की बजाय, उल्लंघन जायज ठहराने या छुपाने को मजबूर होना पड़ता है।

ये मामले दर्शाते हैं कि संयम को केवल नियंत्रण संधियों के माध्यम से नहीं, बल्कि एक साझा विश्वास के जरिए संस्थागत रूप दिया जा सकता है, इसी प्रकार कुछ हथियारों और उनके उपयोग को लेकर बयानबाज़ी को भी पूर्ण अवैध घोषित करना चाहिए। चिंताजनक रूप से, परमाणु विमर्श उल्टी दिशा में जा रहा है। धमकी और इस्तेमाल की वर्जना को मज़बूत करने की बजाय, चुप्पी व बेपरवाही उसे खोखला कर रही है। कलंक के जिस डर ने बारूदी सुरंगों और रासायनिक हथियारों का उपयोग रोके रखा है, वह परमाणु हथियारों के मामले में बेपरवाही का सामान्यीकरण करने से प्रभाव खो सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर की सीख- भारत का अपना इतिहास एक शक्तिशाली प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। ऑपरेशन सिंदूर में, जब पाकिस्तानी सेना कमज़ोर पड़ी और तनाव बेहद था, भारत के पास युद्ध को विस्तार देने की पूरी क्षमता थी। फिर भी उसने नपा-तुला संयम चुना। लक्ष्यों पर सटीक प्रहार किया, टकराव में विस्तार किये बिना ऑपरेशन खत्म कर दिया। यह कमज़ोरी नहीं थी; आवेग के वशीभूत होने के बजाय सिद्धांत पर अमल करना था। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि परमाणु युग की शासन प्रणाली गैर-जिम्मेवार हुए बगैर दृढ़ रह सकती है। यह भी कि संयम की शक्ति भरोसा कम करने के बजाय मज़बूत करती है।

संयम के व्याकरण की पुनर्स्थापना- चिंतन करना बेशक पहले जरूरी होता है, लेकिन कार्रवाई इंतजार नहीं सकती। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, माइक्रोफोन पर गैर-जिम्मेदार बयानबाजी से परमाणु युग की सुरक्षा के वास्ते, दुनिया को अपने सिद्धांतों और परमाणु शब्दावली में अनुशासन बहाल करना होगा।

जे. एसएस मेहता

जरूरी है बहुआयामी दृष्टिकोण- मेजबान देश को अपनी भूमि पर परमाणु ब्लैकमेल का विरोध करना चाहिए, स्पष्ट करते हुए कि ऐसी बयानबाजी अस्वीकार्य है। संयुक्त राष्ट्र, पी-5, क्षेत्रीय मंच जैसी संस्थाओं को इसकी पुष्टि अवश्य करनी चाहिए कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी सामूहिक निंदा की मांग करती है, विनम्र चुप्पी की नहीं। राजनयिक मंच संयम के स्थान के रूप में बरते जाएं। कोई प्रेस वार्ता या आधिकारिक यात्रा व्यक्तिगत मंच नहीं होता; यह एक देश के दूसरे देश से संवाद का पटल होता है। नागरिक समाज और मीडिया में भी संयम की शब्दावली की समझ जरूरी है, बेकाबू परमाणु बयानों को उग्रता बढ़ाने के रूप में पेश करना चाहिए। रक्षा प्रतिष्ठान भी राजनीतिक नेतृत्व को नियमित रूप से जानकारी देकर उन्हें निष्पक्ष, ऐतिहासिक रूप से स्थिर और खतरे के आकलन से अवगत कराए, ताकि नेताओं में सरसरी तौर पर ही, लेकिन परमाणु संबंधी अनौपचारिक बयानबाजी की कीमत चुकाने की समझ बन सके। यह अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाना नहीं, बल्कि यकीनी बनाना है।

सिद्धांत पालना- जब सिद्धांत मौन पड़ जाएं, सत्ता उनसे खिलवाड़ करने लगती है। शब्दावली पर काबू न रहने पर,यह अपनी बोली बोलने लगती है- धमकी की भाषा। यह ऐसी बोली है जिसमें दुनिया कभी भी पारंगत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने का मतलब होगा मुख से तबाही निकलना। परमाणु ब्लैकमेल के समक्ष दुनिया की चुप्पी तटस्थता नहीं, बल्कि मिलीभगत है। इस प्रवृत्ति को उलटना एक विकल्प न होकर अस्तित्वगत अनिवार्यता है।

ओवरटूरिज्म के खिलाफ मुखर स्थानीय विरोध

निस्संदेह, टूरिज्म हो या ओवरटूरिज्म, इससे देशों, राज्यों, नगरों या गांवों की आर्थिकी बढ़ने की संभावनाएं रहती ही हैं। मगर पूरे विश्व में सभी देशों के स्थानीय निवासी ओवरटूरिज्म से खुश नहीं हैं। विशेषकर यूरोप में लोकप्रिय पर्यटक नगरों में अतिशय पर्यटन का विरोध हो रहा है। भारतीय पर्यटन नगरियों में भी पर्यटकों की भारी भीड़, उनके व्यवहार, जाम, उपभोक्ता सामग्रियों की बढ़ती मांग और कूड़ा-कचरे के अंबार के कारण भारत भी देर-सबेर ओवरटूरिज्म के विरोध से अछूता नहीं रहेगा। यूरोप में ओवरटूरिज्म का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे घरों के किराए बढ़ गए हैं, हमारी गलियां भीड़भरी हो गई हैं और स्थानीय संस्कृति का क्षरण हो रहा है। भारत में भी अत्यधिक पर्यटनग्रस्त नगरों के नागरिक ऐसा अनुभव कर रहे हैं।

दरअसल, ओवरटूरिज्म की असली कीमत स्थानीय लोग चुका रहे हैं। जाम में फंसकर हर काम में अतिरिक्त समय लग रहा है। आने-जाने में देरी से ज़रूरी काम छूट जाते हैं या टालने पड़ते हैं, जिससे आर्थिक हानि होती है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। यह वह लागत है, जो पर्यटन से होने वाली आय का बखान करने वाली सरकारों और हितधारकों के आकलन में शामिल नहीं होती।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, शिमला में 20 से 23 जून के बीच 60,000 पर्यटक वाहन नगर में दाखिल हुए। इसी प्रकार, जून, 2025 में देहरादून से मसूरी मार्ग पर सामान्य दिनों में जहां प्रतिदिन 4,000 से 8,000 वाहन चलते थे, वहीं अब सप्ताहांत में यह संख्या 15,000 तक पहुंच रही है।

यूरोप में ओवरटूरिज्म के खिलाफ आंदोलन तेज़ हो गया है, विशेषकर इटली, स्पेन और पुर्तगाल में यह विरोध जोर पकड़ रहा है। 'घर जाओ पर्यटक', 'एक पर्यटक का बढ़ना, एक स्थानीय का कम होना' जैसे पोस्टर आम हो गए हैं। लोगों का कहना है कि उनका जीवन दूभर हो गया है। इसके अलावा बड़े-बड़े होटलों के निर्माण और विस्तार का विरोध हो रहा है। 15 जून को यूरोप के कई हिस्सों में बड़े विरोध-प्रदर्शन हुए। बार्सिलोना इन प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र बन चुका है। वहां प्रदर्शनकारियों ने वाटर गनों से पर्यटकों को निशाना बनाया।

बार्सिलोना की जनसंख्या मात्र 16 लाख है, जबकि 2024 में वहां 2.6 करोड़ पर्यटक आए। लोग कह रहे हैं कि अब जहां नज़र डालें, वहां पर्यटक ही दिखते हैं। 'आपका सामना ऐसे लोगों से होता है, जिन्हें आप नहीं जानते और जो आपको नहीं जानते,'कृस्थिति असहायता का भाव पैदा करती है।

पिछले वर्ष यूरोप में कुल 7470 लाख पर्यटक आए। ग्रीस में देश की जनसंख्या से चार गुना अधिक पर्यटक पहुंचे। अधिकांश प्रमुख पर्यटक शहरों में स्थानीय जनसंख्या से सात-आठ गुना अधिक पर्यटक आ रहे हैं, जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव है। भारत में भी यात्रियों के पारंपरिक मूल्यों की दृष्टि से अनुचित आचरण और व्यवहार से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

उत्तराखंड के समाज विज्ञानियों का कहना है कि इस साल के टूरिस्ट सीजन और चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जो वीडियो, तस्वीरें और खबरें सामने आईं, वे दर्शाती हैं कि गांवों के किसान रील बनाने आने वाली उद्दंड पर्यटक भीड़ से परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की है। वे कहते हैं कि इससे खेतों को नुकसान हुआ है और निजता का भी उल्लंघन हुआ है।

पर्यटकों के मनमाने ढंग से जहां-तहां रुकने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से पर्यटक मार्गों पर दुर्घटनाओं का जोखिम लगातार बढ़ रहा है। सड़क मार्ग पर लगने वाला जाम तो ओवरटूरिज्म की शुरुआत भर है। इसका असली असर तब दिखता है जब कोई पर्यटक नगरी के भीतर जाकर सार्वजनिक स्थानों पर गुंडागर्दी, सड़कों पर हादसे, शराब और ड्रग्स का सेवन व अपराध तेजी से बढ़े हैं। केरल के वायनाड जिले में एक बांध के पास के प्रमुख पर्यटन स्थलों कृजैसे झीलों, झरनों, नदियों, पार्कों या म्यूज़ियमों कृमें पहुंचता है। वहां की भीड़, शोरगुल और प्रदूषण स्थानीय पर्यावरण और शांति को गहरे प्रभावित करते हैं। हजारों पर्यटकों और सैकड़ों वाहनों की आवाजाही से न तो शांति रह गई है, न ही स्वच्छ वायु। प्लास्टिक कचरा और अन्य प्रदूषण अलग से संकट पैदा कर रहे हैं।

सरकारें कैसे सोचती हैं कि स्थानीय लोग थोड़े आर्थिक लाभ के लिए अपनी शांति और पर्यावरण का बलिदान देने को तैयार रहेंगे? मान लिया जाए कि पर्यटन से पैसा आता है, पर वह लाभ मुख्यतः बाजार के कुछ दुकानदारों तक ही सीमित रहता है। ये दुकानदार, सामान की कमी बताकर ओवर रेटिंग करते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इन ऊंची कीमतों का असर केवल पर्यटकों पर ही नहीं, बल्कि वहीं रहने वाले स्थानीय लोगों पर भी पड़ता है। होटल व्यवसायी महंगे सामान खरीदकर उसका खर्च पर्यटकों से वसूल सकते हैं, लेकिन घर चलाने वाली एक आम गृहिणी के लिए यह महंगाई एक बड़ा बोझ बन जाती है। वह परिवार की जरूरतें पूरी करने हेतु खरीदारी करती है।

पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता भार ओवरटूरिज़्म का एक गंभीर पहलू है। यह समस्या केवल हिमालयी राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में भी देखी जा रही है। भारत के पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों, जो अधिकतर ईको-संवेदनशील हैं, पर भी ओवरटूरिज़्म का दबाव स्पष्ट दिखा है।

केरल के वायनाड जैसे क्षेत्र, जो भूस्खलन व वन्यजीवों के आक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील हैं, वहां भी अनियंत्रित पर्यटक गतिविधियां चिंता का विषय बनी हुई हैं। तमिलनाडु के पहाड़ी स्थलों पर प्रतिदिन लगभग 20,000 वाहन पहुंच रहे हैं, जिससे नीलगिरी जैसे क्षेत्रों में सूखे और पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति बन रही है। कोर्ट के निर्देशों के तहत यहां ई-पास प्रणाली लागू करके पर्यटकों की संख्या सीमित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में सड़कों की 'बियरिंग कैपेसिटी' का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। केरल और तमिलनाडु में भी न्यायालयों ने पर्यावरणीय संरक्षण के संदर्भ में सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं। दरअसल, ईको-संवेदनशील पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटक वहन क्षमता के मानक और आकलन की पद्धतियां सामान्य पर्यटन नगरों से भिन्न होंगी। वहां की प्रकृति के अनुसार पर्यटक संख्या और प्रतिबंधों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली

उत्तराखंड की कुल जनसंख्या लगभग 1.2 करोड़ है, जबकि हर वर्ष यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 6 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यानी राज्य की जनसंख्या से लगभग पांच गुना अधिक पर्यटक यहां आते हैं। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने हाल ही में कहा था कि लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों में स्थानीय लोग प्रतिदिन 5 से 10 लीटर पानी में जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन बाहरी पर्यटकों को प्रतिदिन 200 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यह पारिस्थितिकीय भार है।

यूरोपीय पर्यटन प्रभावित शहरों में भीड़ नियंत्रण व सांस्कृतिक-सामाजिक संरचना को बचाने हेतु विशेष प्रबंधन योजनाएं लागू की जा रही हैं। स्पेन, इटली और ग्रीस जैसे देश अब 'नेचर-बेस्ड टूरिज़्म' को बढ़ावा दे रहे हैं। फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे देश ईको टूरिज़्म और 'स्लो व इमर्सिव टूरिज़्म' को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही, 'जीरो कार्बन ट्रांसपोर्ट' यानी पर्यावरण-अनुकूल यात्रा विकल्पों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पीएम आवास योजना से वंचित ग्रामीणों ने किया जोरदार हंगामा

माही की गूंज, रतलाम।

जिला पंचायत रतलाम के मुख्य द्वार पर ग्राम घटला सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 6 सालों से ग्राम घटला के किसी भी हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। ग्रामीण महिलाएँ और पुरुष जिला पंचायत के गेट पर जमीन पर बैठकर नारेबाजी करते रहे और गेट को बंद कर दिया।

एडिशनल सीईओ निर्देशक शर्मा और ग्रामीणों के बीच में तीखी बहस

इस दौरान जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ निर्देशक शर्मा और ग्रामीणों के बीच पुलिस की मौजूदगी में तीखी बहस हो गई। ग्रामीणों ने मांग की कि उन्हें तुरंत पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार शिकायत और आवेदन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब मजबूरी में उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा।

एडिशनल सीईओ निर्देशक शर्मा ने ग्रामीणों से कहा कि, यह तरीका गलत है, आप गेट बंद करके शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हो। सरकार की ओर से ग्राम घटला सहित जिले के 6 गांवों के नाम तकनीकी दिक्कत के कारण सूची से हट गए थे। अब सुधार की प्रक्रिया चल रही है, पहले ही 274 नाम सूची में जोड़े जा चुके हैं और बाकी भी जल्द जुड़ जाएंगे।

6 साल से नहीं मिला एक भी लाभ

हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि, वे 6 साल से लगातार परेशान हैं और अब आश्वासन नहीं, लाभ चाहिए। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर समझाइश दी और गेट खुलवाया गया। इसके बाद ज्ञापन सौंपने के दौरान भी ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, लेकिन ज्ञापन ले लिया गया।

प्रशासन का कहना है कि, जिले के 6 गांवों में तकनीकी खराबी की वजह से पीएम आवास योजना का लाभ हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाया था, जिसे अब जल्द ठीक कर दिया जाएगा।

शासकीय स्कूल के शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से पीटा

माही की गूंज, खाचरोद।

माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि ताकि उनका भविष्य बन सके, लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील के गांव बुरानाबाद में एक शासकीय हाई स्कूल के शिक्षक ने एक छात्र को जिंदगी में मौत से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। शिक्षक ने कक्षा 9वीं के छात्र की इतनी बेहरमी से पिटाई की वह दहशत में आ गया स्कूल से आने के बाद बेहोश हो गया। परिजन छात्र को शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती किया गया। इधर बुधवार को परिजनों ने शिक्षक के खशिलाफ पुलिस थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

शिक्षक राजेश जैन निवासी नागदा ने छात्र शैलेंद्र पुत्र धर्मेंद्र जटिया निवासी राधा कृष्ण कॉलोनी खाचरोद को मंगलवार दोपहर 3 बजे विद्यालय के एक अलग कक्ष में ले जाकर जमकर पीटा। जिससे छात्र बेहोश हो गया। इसी हालात में छात्र को भर्ती कराया गया लगभग 3 घंटे बाद उसे होश आया। बुधवार को छात्र को रतलाम रैफर किया गया है।

ग्रामीण वासियों के मुताबिक शिक्षक जैन द्वारा आए दिन विद्यार्थियों के साथ इस तरह की मारपीट की जाती है। आखिर क्या कारण था कि शिक्षक ने छात्रा को अलग कमरे में ले जाकर मारा। यदि इसमें कोई गलती हुई थी तो उसे क्लास रूम में ही मारना था। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से शिक्षक जैन बुधवार को स्कूल भी नहीं पहुंचे और ना ही किसी का फोन उठा रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस थाना खाचरोद, जिला अधिकारी शिक्षा उज्जैन और एसपी उज्जैन को शिकायत की है।

बाल संप्रेषण गृह में मनाया गया विश्व मानवता दिवस

माही की गूंज, रतलाम।

आनंद विभाग रतलाम द्वारा विश्व मानवता दिवस बाल संप्रेषण गृह में आयोजित किया गया। जिला समन्वयक सीमा अग्निहोत्री ने बताया कि, एक मानवीय समाज के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आस-पास के लोगों की संकट में मदद करें और उन्हें सम्मानजनक जीवन की परिस्थिति में रहने के अधिकार को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाए। आनंदक विनीता ओझा द्वारा महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी के जीवन की कहानियों के माध्यम से उनको सही राह पर चलने की प्रेरणा दी गई। सीमा अग्निहोत्री द्वारा शांत समय में माता-पिता का वर्तमान चेहरा जब वे यहां है और जब वे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तब का चेहरा देखने को कहा गया। उनके अश्रुओं ने बताया कि वे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं।

मास्टर ट्रेनर पुष्पेंद्र सिंह सिसौदिया ने बालकों से उनकी मां के नाम पूछकर, मां की ममता को महसूस करने के लिए आग्रह किया। बालकों ने बताया कि बाहर जाने के पश्चात परिवार को सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए वे मेहनत करेंगे। बालकों ने ड्राइवर, खेती बाड़ी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फास्ट फूड की शॉप, बिजनेस, स्वयं का रेडीमेड कपड़ों की शॉप और मिठाई की दुकान के माध्यम से अच्छा व्यक्ति बनने की इच्छा जाहिर की। जन अभियान परिषद जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय ने नशे के दुष्परिणाम को एक सच्ची घटना के द्वारा बताया और नशा मुक्ति हेतु संकल्प दिलाया। बालकों की रचनात्मकता हेतु पेंट कलर ब्रश दिए गए जिससे वे परिसर के अंदर की दीवारों, गमले और गणेश जी को अपनी क्रियात्मकता से रंग सके। आनंदम सहयोगी सुरेंद्र अग्निहोत्री और संजय ओझा के सहयोग से आनंदकों ने बालकों की मां के नाम पर बाल संप्रेषण गृह के बाहरी परिसर में नगर निगम रतलाम द्वारा उपलब्ध कराए गए 11 पेड़ का पौधारोपण किया।

एकलव्य छात्रावास में फैला वायरल बुखार, दो दर्जन से अधिक छात्राएं बीमार

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसका ताजा असर बाजना के आदिवासी एकलव्य छात्रावास में देखने को मिला है। यहां वायरल बुखार की चपेट में आकर दो दर्जन से ज्यादा छात्राएं बीमार हो गईं। इनमें से 12 छात्राओं की हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत बाजना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पिछले कुछ दिनों से जिले में लगातार बारिश हो रही है जिससे मौसम में आई नमी के कारण वायरल और अन्य मौसमी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। एकलव्य छात्रावास में बीमारी फैलने की खबर मिलते ही प्रशासन और छात्रावास प्रबंधन सक्रिय हो गया। बीमार छात्राओं को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया गया। वहीं कुछ अन्य छात्राओं का उपचार छात्रावास परिसर में ही किया जा रहा है।

युवक-युवती की संदिग्ध मौत, शव यात्री प्रतीक्षालय में मिले

माही की गूंज, उज्जैन/नागदा।

जिले के नागदा से लगभग 2 किमी दूर गांव डाबरी में बुधवार को एक युवक और एक युवती का शव मिला। युवक की जेब से कीटनाशक दवाई का पाउच मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर कार्यवाही को अंजाम दिया। बिड़ला ग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार के मुताबिक दोनों ताल-आलोट जिला रतलाम के निवासी है। युवती की उम्र 17 वर्ष 10 माह तथा युवक की उम्र लगभग 18 वर्ष है। संभावना है कि दोनों ने कीटनाशक दवा को पीकर आत्महत्या की है। मामला प्रेमप्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है।

युवती के परिजनों ने मंगलवार केा थाना आलोट जिला रतलाम में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवक शाम को अपने खेत पर कीटनाशक दवा छिड़कने गया था और बुधवार सुबह दोनों के शव यात्री प्रतीक्षालय में मिले, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व शुरू, आठ दिन रोजाना होंगे विभिन्न कार्यक्रम

माही की गूंज, मंदसौर।

श्री केशरिया आदिनाथ श्रीसंघ अध्यक्ष दिलीप डांगी, सचिव संदीप धींग ने बताया कि, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व बुधवार, 20 अगस्त से 27 अगस्त तक रहेंगे। इस दौरान 8 दिवस में प्रतिदिन श्रीसंघ एवं चातुर्मास समिति के द्वारा चौधरी कॉलोनी स्थित रूपचांद आराधना भवन में विविध कार्यक्रम होंगे।

प्रातः 6 बजे प्रतिक्रमण, 6.45 बजे प्रभुजी की प्रतिमाओं का पक्षाल एवं अभिषेक, 7 बजे केसर पूजा होगी। प्रवचन का समय प्रातः 8.30 से 10.30 बजे तक होगा, जिसमें शास्त्र वाचन एवं प्रवचन दोनों होंगे। सायं 7 बजे प्रतिक्रमण होंगे। महिलाओं एवं पुरुषों का स्थान अलग-अलग रहेगा। रात्रि 8.30 बजे प्रभु भक्ति (भक्ति संध्या) होगी। भगवान महावीर एवं तीर्थंकरों का जन्मवाचन 24 अगस्त रविवार को प्रातःकाल शास्त्र वाचन के बाद होगा। जन्मवाचन पूर्व श्रीसंघ के द्वारा वर्षभर की धार्मिक गतिविधियों की वार्षिक बोलिया भी रूपचांद आराधना भवन में लगेगी। जन्मवाचन के बाद पालनाजी का जुलूस भी निकलेगा। संवत्सरी पर्व 27 अगस्त को मनेगा। 28 अगस्त को सामूहिक क्षमापना पर्व भी मनेगा तथा सामूहिक पारणा भी होगा।

विश्व मच्छर दिवस पर जनजागरूकता रैली आयोजित

माही की गूंज, मंदसौर।

विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर बुधवार को नरसिंहपुरा क्षेत्र में जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जिला मलेरिया विभाग द्वारा आयोजित की गई। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. दीपा पाठक ने बताया कि प्रतिवर्ष 20 अगस्त विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आमजन को मच्छरों की उत्पत्ति स्थल एवं स्त्रोतों के प्रति जागरूक करना है, ताकि मच्छरजनित स्त्रोतों को नष्ट या नियंत्रित कर मच्छरों से बचाव किया जा सके और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से सुरक्षा मिल सके। रैली में शासकीय माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा के छात्र-छात्राओं एवं स्टाफ ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को मच्छरों से होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि से बचाव के उपाय बताए गए। साथ ही क्षेत्र में लार्वा सर्वे एवं दवाइयों का छिड़काव भी किया गया।

औद्योगिक क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराएं- कलेक्टर

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में कलेक्टर अदिती गर्ग की अध्यक्षता में जिला उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र शामगढ़ एवं पानपुर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने तथा आनलाइन माध्यम से भूखंड आवंटन संबंधी विषय पर विस्तार से चर्चा की गई।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क आदि प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाएं। औद्योगिक क्षेत्र शामगढ़ में न्यूनतम 500 वर्ग मीटर से अधिकतम 1500 वर्ग मीटर के कुल 302 भूखंड तथा पानपुर औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम 500 वर्ग मीटर से अधिकतम 9000 वर्ग मीटर के कुल 68 भूखंड तैयार किए गए हैं।

बैठक में मंदसौर विधायक विपिन जैन, सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक मंगल रायकवार एवं जिले के उद्योगपति उपस्थित रहे। भूमि आवंटन हेतु पात्र इकाइयों को निर्धारित आवेदन प्रपत्र, चेकलिस्ट अनुसार अभिलेख एवं 5,000 रुपये आवेदन शुल्क जमा कर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इकाई को प्रचलित प्रीमियम का 25 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करनी होगी। आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। प्रथम वर्ष में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमियों हेतु 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षित रहेंगे।

अविकसित भूमि का आवंटन

अविकसित भूमि का आवंटन केवल मध्यम उद्योगों को किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में लघु उद्योगों को भूमि देने हेतु शासन से प्रशासकीय स्वीकृति आवश्यक होगी। संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

आवारा कुत्तों का कहर, युवक का चेहरा नौचा

माही की गूंज, जावरा।

जिले के जावरा बस स्टैंड पर मंगलवार को सुबह मिला था युवक का शव। पुलिस के मुताबिक युवक के मुंह को कुत्तों ने दर्दनाक नोचा हैं। पुलिस का कहना हैं कि अब मृतक की पोस्मार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होगा कि मृतक युवक की मौत कैसे हुई और उसे कुत्तों ने मौत से पहले नोचा या फिर शव को नोचा ये फिलहाल अनसुलझी बात हैं जो पोस्मार्टम रिपोर्ट में ही साफ़ हो पाएगा।

ग्रामीणों में आवारा कुत्तों का दहशत

रतलाम के जावरा बस स्टैंड पर मंगलवार की सुबह एक युवक का शव मिला जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने शहर थाना पुलिस को दी मौके पर थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहीं पुलिस के मुताबिक युवक के मुंह को आवारा कुत्तों ने दर्दनाक तरीके से नोचा है। युवक की पहचान पप्पू लाल पिता पूनम चंद चंद्रवंशी के रूप में हुई हैं।

घटना की जानकारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए शहर थाना पुलिस ने रतलाम से एफएसएल टीम को बुलवाया और एफएसएल टीम जावरा बस स्टैंड पर घटनास्थल पहुंची जहां उन्होंने घटनास्थल से जांच के लिए सैंपल लिए। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर युवक की मौत कैसे हुई है इस जांच में लगी हुई है । देश की ठंड तक आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित है और अब इस घटना ने रतलाम जिले के अधिकारियों को आवारा कुत्तों पर एक्शन लेने पर और उनके बारे में सोचने पर चिंतित कर दिया है। अब देखना यह है कि रतलाम जिले में आवारा कुत्तों पर कब तक लगाम लगेगी।

13 दिन डिजिटल कैद में बुजुर्ग दंपत्ती, 50 लाख रुपए की ठगी

माही की गूंज, खंडवा।

तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद सायबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला खंडवा जिले के पंधाना नगर का है, जहां बुजुर्ग दंपती को 13 दिन तक डिजिटल कैद में रखकर 50 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर फोन किया और हत्या, अपहरण व धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में नाम आने का झांसा दिया। इसके बाद दंपती को डराकर घर में बंद कर दिया और बैंक जाकर एफडी तुड़वाने तक मजबूर कर दिया।

नकली पुलिस बनकर कराया खाता खाली

पीड़ित दंपती का कहना है कि उनका पंधाना में बर्तनों का कारोबार है और वे अकेले रहते हैं। 18 जुलाई को उनके मोबाइल पर मुंबई के कोलाबा थाने से पुलिस अधिकारी बनकर कॉल आया। ठगों ने कहा कि इस नंबर वाली सिम से हत्या व अपहरण जैसी वारदात हुई है और जांच में सहयोग करना होगा।

ठगों ने वीडियो कॉल पर पूरा थाना और वर्दी पहने नकली पुलिसकर्मी तक दिखाए। कहा कि यदि आप घर में नहीं रहोगे तो थाने आना पड़ेगा। बुजुर्ग होने के कारण दंपती ने घर पर ही रहने की बात कही। इसके बाद 21 जुलाई को ठगों ने उनके पैसों की जांच करने के नाम पर बैंक जाकर एफडी तुड़वाने के लिए कहा।

दंपती ने 30 लाख रुपए की एफडी तोड़कर बताए गए खाते में जमा कर दी। कुछ दिन बाद फिर उन्हें बैंक भेजकर 19 लाख 50 हजार रुपए की एफडी तुड़वाई गई। ठगों ने बैंक मैनेजर को शक न हो, इसके लिए दंपती को कहने के लिए कहा कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे चाहिए।

जमानत के नाम पर भी 70 हजार की ठगी, जन्माष्टमी पर खुला राज

ठगों ने दंपती को इतना डरा दिया कि वे लगातार 13 दिन तक घर में कैद रहे। 27 जुलाई को वीडियो कॉल पर एक शख्स ने खुद को डीएसपी बताया और कहा कि आपकी जमानत करवानी है। इस बहाने 70 हजार रुपए और वसूल लिए गए। 16 अगस्त तक दंपती ने किसी को घटना की जानकारी नहीं दी। जन्माष्टमी पर महिला मायके गई और डरते-डरते भाई को पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद परिवार ने सायबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की। खंडवा सायबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर प्रवीण आर के अनुसार, मामला सायबर ठगी का है और पीड़ित दंपती की शिकायत पर जांच चल रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी नवंबर 2024 में खंडवा जिला अस्पताल की नर्स को इसी तरह फर्जी कॉल और वीडियो कॉल दिखाकर 21 घंटे तक कमरे में बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया था। उस समय नर्स को भी ड्रग्स तस्करी में फंसाने की धमकी दी गई थी, हालांकि ठग पैसे ट्रांसफर कराने में सफल नहीं हो पाए थे।

सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई राजीव गांधी की जयंती

माही की गूंज, बड़वानी।

कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री ''राजीव गांधी'' की 81वीं जयंती को 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाया। शहर के शुभम पैलेस में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

राजीव गांधी वर्ष 1984 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। उनकी सरकार ने लोकसभा में भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। वे भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में देश में 'कंप्यूटर क्रांति' की शुरुआत हुई और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदान का अधिकार मिला।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानेश चौधरी ने कहा कि, राजीव गांधी ने सूचना क्रांति की नींव रखी। उन्होंने पंचायती राज को मजबूती दी और युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाया। राजीव गांधी ने युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया। उन्होंने भारत को तकनीकी और डिजिटल युग की ओर अग्रसर किया।

उनकी नीतियों ने देश को 21वीं सदी के लिए तैयार किया। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर उन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को और गहराई प्रदान की।

कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव, नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष राकेश जाधव सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नगर परिषद अध्यक्ष पर मनमानी और तानाशाही के आरोप

माही की गूंज, बड़वानी।

नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष राकेश जाधव सहित कई पार्षदों ने बुधवार को नगर परिषद अध्यक्ष पर मनमानी और तानाशाही का आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।

पार्षदों का आरोप है कि अध्यक्ष को मिले प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे जनप्रतिनिधियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है।

ज्ञापन में बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 27 सितंबर आदेश क्रमांक 3336 के अनुसार परिषद की सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल में निहित कर दी गई हैं। पार्षदों का आरोप है कि अध्यक्ष अपनी मर्जी से जब चाहें तब 'प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल' के सदस्यों को हटा या नियुक्त कर लेते हैं, जिससे परिषद केवल एक कठपुतली बनकर रह गई है।

नेता प्रतिपक्ष राकेश जाधव ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि सरकार पूर्व की तरह परिषद को पुनः वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दे, ताकि चुने गए पार्षदों की भूमिका सार्थक हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अध्यक्ष मनमाने निर्णय ले रहे हैं, जिससे जनता के बीच पार्षदों की छवि धूमिल हो रही है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियमों को भी कठिन बना दिया गया है। अब अविश्वास प्रस्ताव दो-तिहाई के बजाय तीन-चौथाई पार्षदों के मतों से ही पारित होगा और इसे दो वर्ष की बजाय तीन वर्ष बाद ही लाया जा सकेगा।

पार्षदों का कहना है कि इन बदलावों से अध्यक्ष निरंकुश हो गए हैं और जनहित के कार्यों के बजाय अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मनमाने फैसले ले रहे हैं।

पार्षदों ने सरकार से अपील की है कि नगर के उचित विकास के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनः बहाल किया जाए और अध्यक्ष की तानाशाही पर तुरंत रोक लगाई जाए।

शादी के 17 दिन बाद दुल्हन गहने और नकदी लेकर फरार

माही की गूंज, खंडवा

एक युवक के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। युवक ने इंदौर निवासी युवती से दोस्ती की और बाद में विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के बाद भी युवती अपने पूर्व प्रेमी के संपर्क में रही और युवक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

विवाह के 17 दिन बाद ही युवती अपने घर लौट गई। इसके साथ ही वह 5 लाख रुपए के गहने और 2.5 लाख रुपए नकद भी ले गई। इसके बाद उसने युवक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

तीन साल तक चलता रहा शोषण

करीब तीन साल तक युवक युवती की ब्लैकमेलिंग का शिकार होता रहा और उसके पीछे लगभग 20 लाख रुपए खर्च कर बैठा। युवक ने पुलिस से लेकर एसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी तक शिकायत की।

थाना मोघट रोड टीआई धीरज धारवाल ने बताया कि, 27 वर्षीय युवक एहतेशाम खान की शिकायत पर इंदौर निवासी युवती के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोप है कि, युवती ने पूर्व प्रेम संबंध छिपाकर विवाह किया और कुछ समय पत्नी के रूप में रहने के बाद नकदी और गहने लेकर भाग गई। इसके साथ ही उसने पूर्व प्रेमी के साथ दूसरा संबंध बनाए रखा और युवक को दहेज प्रताड़ना के मामले में फंसाने की धमकी देकर रुपए की वसूली की।

वकील के जरिए भी धमकी

गुलशन नगर निवासी एहतेशाम खान ने बताया कि, 12 फरवरी 2021 से 31 मई 2024 तक युवती ने उसे लगातार धोखा दिया। युवती ने वकील के जरिए भी धमकाया और इंदौर पुलिस थाने में उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज कराया। जांच में यह भी सामने आया कि, युवती हनीट्रैप गिरोह से जुड़ी है और अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चुकी है।

पर्यावरण भी प्राथमिकता हो डिजिटल युग में

शिक्षा वह माध्यम है, जिसके सहारे हम तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सकते हैं। आज की दुनिया में कृत्रिम मेधा का बोलबाला है। रोबोट मनुष्य का स्थान लेने लगे हैं, क्योंकि संपन्न निवेशकों को लागत प्रबंधन में यही उपयुक्त लगता है। ऐसे में शिक्षा को यह सुनिश्चित करना होगा कि ज्ञान सही दिशा में पहुंचे, न कि डीपफेक और साइबर अपराध जैसे खतरनाक गलियारों में खो जाए।

यदि सर्वेक्षण बताते हैं कि बच्चों को दस तक का पहाड़ा या प्रतिशत निकालना भी नहीं आता, तो सवाल उठता हैकृवे इस बदलती दुनिया के ज्ञान से कैसे कदम मिला पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि भारत में शिक्षा क्रांति का अर्थ केवल व्यावसायिक विस्तार नहीं है। शिक्षा संस्थानों का निर्माण करते समय पर्यावरणीय प्रभावों का संज्ञान लेना आवश्यक है। 29 जनवरी, 2025 को केंद्र सरकार की एक अधिसूचना कोर्ट के विचाराधीन हुई, जिसमें औद्योगिक शेड, स्कूल, कॉलेज और छात्रावास जैसी परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरण मंजूरी से छूट प्रदान की गई थी।

अधिसूचना में यह स्वीकार किया गया कि 20,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में निर्माण कार्य पर्यावरण को प्रभावित करेगा, लेकिन यह भी कहा गया कि इन संस्थानों का राष्ट्रीय विकास में इतना महत्व है कि इन्हें पूर्व मंजूरी से मुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन अत्यंत आवश्यक है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो घुटन, हरित क्षेत्र की कमी, खेल के मैदानों का लोप और शिक्षा के नाम पर व्यापार का विस्तार देखने को मिलता है।

बीते वर्षों में अनेक राजनीतिक दलों ने शिक्षा क्रांति के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए हैं। यह कहा जाता है कि शिक्षा केवल निजी पब्लिक स्कूलों की बंधक नहीं होनी चाहिए। नीति यह होनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों को इतना सक्षम बनाया जाए कि माता-पिता को अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने की कोई जल्दबाज़ी न रहे। लेकिन इस लक्ष्य के बावजूद, सरकारी स्कूल अब भी उस स्तर को नहीं छू पा रहे हैं, जिसकी कल्पना करके हमने निजी स्कूलों के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश की थी।

सवाल यह है कि इतने प्रयासों के बावजूद, शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेशक क्यों प्रवेश कर रहे हैं? क्या शिक्षा अब सेवा नहीं, एक लाभकारी व्यवसाय बन गई है? अब तो स्कूलों के बीच नए स्कूल खोलने की परंपरा-सी बन गई है। पहले जहां खेल मैदान हुआ करते थे, वहां अब नर्सरी और प्री-नर्सरी की कक्षाएं बन रही हैं।

कहा जाता है कि निजी पब्लिक स्कूल एक लाभकारी सौदा बन चुके हैं। हर वर्ष इन स्कूलों की फीस और अन्य शुल्क बढ़ते जाते हैं। अब प्राइमरी कक्षाओं के साथ-साथ नर्सरी और प्री-नर्सरी भी 'खुलने' लगी हैंकृजिनका मकसद शिक्षा कम, व्यापार अधिक लगता है।

संभावना है कि भविष्य में पुरानी शिक्षा प्रणाली अप्रासंगिक हो जाएगी और एक नई 'डिजिटल शिक्षा' उभरेगीकृजो डेटा, एल्गोरिद्म और इंटरनेट के इर्द-गिर्द घूमेगी। ऐसे में स्कूलों में हरियाली, खेल मैदान और खुलापन खत्म न हो जाए, यह चिंता का विषय है।

अब हम ऐसे प्राइमरी स्कूलों की संभावनाएं देख रहे हैं, जहां बच्चों को आरंभ से ही डिजिटल और कृत्रिम मेधा की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इस दौड़ में कहीं पर्यावरण बलि का बकरा न बन जाए। कहीं स्कूलों की हरियाली समाप्त न हो जाए। कहीं खेल मैदान बहुमंजिला इमारतों की भेंट न चढ़ जाएं।

कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह मानना कि केवल कुछ दिशा-निर्देशों का पालन कर लेने से पर्यावरण सुरक्षा हो जाएगी, पर्याप्त नहीं है। योजनाएं जब विस्तार लेती हैं तो व्यावसायिक हित हावी हो जाते हैं, और विशेषज्ञों की राय की अनदेखी शुरू हो जाती है।

सुरेश सेठ

पीठ ने माना कि स्कूल, छात्रावास व अन्य शैक्षणिक संस्थान पर्यावरणीय कानूनों के अधीन रहें और उन्हें पूर्व मंजूरी की अनिवार्यता से मुक्त न किया जाए। अधिसूचना में जो छूट दी गई थी, वह दोहरी मंजूरी प्रणाली में से पर्यावरणीय मंजूरी को हटा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन संरक्षित क्षेत्रों और प्रदूषित इलाकों में पर्यावरण मूल्यांकन की प्रक्रिया को कमजोर करता है। इस छूट के पीछे कोई मजबूत तर्क नहीं है, केवल यह संभावना है कि यह निजी शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा देने का एक औजार बन जाए।

कोर्ट का संदेश साफ हैकृशिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण में। भावी पीढ़ी प्रदूषण और अंधाधुंध निर्माण की शिकार न बने, यही सुप्रीम कोर्ट और हर सजग नागरिक की अपेक्षा है।

फ्रिज में कटे रखे टुकड़े, केरल स्टोरी के स्लोगन, उज्जैन में लव जिहाद की झांकी पर बवाल

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले में भगवान शिव शंकर की श्री मनकामेश्वर मंदिर से निकलने वाली झांकी के साथ लव जिहाद की झांकी पर प्रसासन की रोक लगाने पर हिन्दू संगठन कार्यकर्ताओं और हिन्दू समाज के लोगों ने जमकर बवाल काटा ओर झांकी निकालने की बात पर अड़ गए।

बताया जा रहा है कि लवजिहाद की झांकी में प्रतीकात्मक रूप से एक लड़की को फ्रिज में काट कर बताया गया और केरल स्टोरी सहित अन्य स्लोगन बैनर पर लिखे गए थे। इस झांकी की शिकायत किसी ने पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और झांकी को सवारी से हटवाया गया।

पुलिस प्रशासन के इस प्रकार के रवैये से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में रोष उत्पन्न हो गया। इसी बात को लेकर हिन्दू समाज के लोग आक्रोशित हो गए, मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल,एसडीओपी जेंडेन लिंगजेरपा, डीएसपी भारतसिंह यादव के साथ झारड़ा थाना प्रभारी आनंद भाबोर सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और काफी समझाइश के बाद हिन्दू वादी संगठन में गया और सवारी पुनः श्री मनकामेश्वर मंदिर के लिए शुरू हुई। इस दौरान झांकी को महाबली चौपाटी स्थीत पुलिस चौकी पर रखा गया।

उज्जैन जिले में सावन और भादो महीने में भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकाली जाती है। इस दौरान जिले के आसपास के क्षेत्र में भी स्थित प्रसिद्ध भगवान महादेव की सवारी निकालने की परंपरा बताई जाती है। सोमवार शाम उज्जैन जिले के घोंसला में हर साल की तरह इस साल भी भगवान श्री मनकामेश्वर की शाही सवारी निकाली जा रही थी। सवारी में झांकियां, ढोल, बैंड और अखाड़ों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए थे। जानकारी अनुसार हर साल हिन्दू समाज के युवाओं द्वारा समाज को एकता समरसता का संदेश देते हुए झाकिया निकाली जाती हैं। इस वर्ष भी अलग-अलग प्रकार की झाकियां तैयार कर शाही सवारी में शामील किया गया था। इसमे एक झांकी ग्राम बिछडोद सहित अन्य ग्रमीण क्षेत्रो में हुई लव जिहाद की घटनाओं की पेपर कटींग के साथ स्लोगन से तैयार की गई थी। झांकी में लवजिहाद में प्रतीकात्मक रूप से एक लड़की को फ्रिज में काट कर बताया गया और केरला स्टोरी सहित अन्य स्लोगन बैनर पर लिखे गए। बताया जाता है की इस सवारी को निकालने को लेकर प्रसासन ने मना कर दिया। उसके बाद भी झांकी को निकाला जा रहा था। जिसकी सूचना पुलिस प्रसासन को मिली तो उन्होंने इस झांकी को रोका ओर झांकी को सवारी से हटवा दिया।

झांकी में यह रहा खास

घोसला ग्राम के मध्य में स्थित प्रचिन मनकामनेश्वर छत्री महादेव मंदिर से दोपहर 3 बजे पारंपरीक वेशभुष में अंतिम शाही सवारी में मनकामनेश्वर महादेव ने भक्तों को जगन्नाथ भगवान के रूप में दर्शन दिए। सवारी निकलने से पहले भगवान जगन्नाथ स्वरूप में श्रगार कर आरती की गई। झांकियों में महादेव मंदिर से जगन्नाथ भगवान का रथ और नन्हें बच्चे शिव परिवार का वेश बनाकर निकले। सवारी प्रमुख मार्गो से होती हुई रात्रि 8 बजे मदिर प्रांगण पहुयी जंहा जगह-जगह भक्तो ने मंच व घरो से भगवान का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। मंदिर पुजारी बाबु?लाल उपाध्याय ने महाआरती कर प्रसादी वितरण किया गया सवारी में गराम समीती और ग्राम पंचायत द्वास औ आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों के भक्त उपस्थित थे।

झारड़ा थाना प्रभारी आनंद भाबोर ने बताया कि सोमवार को राघवी थाना क्षेत्र के घोंसला में स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर की राजसी सवारी निकाली गई थी। सवारी में लव जिहाद को लेकर एक झांकी को शामिल किया गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने बगैर अनुमति इस प्रकार की झांकी नहीं निकालने देने की बात कही। इससे हिंदूवादी संगठन के लोग नाराज हो गए ओर इस पर बवाल करने लगे। इस दौरान काफी संख्या में लोग झांकी निकालने की बात पर अड़ गए, हालांकि अधिकारियों ने समझाइश देकर झांकी को हटाया दिया।

पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।

जनपद पंचायत सभागार चन्द्रशेखर आजाद नगर में बुधवार को ÷पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0÷ विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत इंदरसिंह पटेल के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण सह कार्यशाला में जनपद पंचायत के सभी ग्राम पंचायतों के सचिव एव रोजगार सहायक और लाइन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के प्रारंभ में माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया। उक्त प्रशिक्षण अब्बास जाम्बुवाला ने ग्राम पंचायतों के सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण के 9 थीम आधारित दृष्टिकोण पर विस्तृत चर्चा की गई। डीसीएफ (डेटा कलेक्शन फॉर्मेट) क्या हैं? कहां से प्राप्त होगा और उपयोग क्या है? के बारे में विस्तृत समझाया गया। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में डेटा एंट्री के लिए आवश्यक 151 प्रश्नोत्तरी का प्रोजेक्टर पर प्रदर्शन एवं उसके उपयोग पर विस्तृत चर्चा कर पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल में शीघ्र अति शीघ्र डेटा एंट्री करने के लिए बताया गया। तथा ऑनलाइन डाटा इंट्री के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। समस्त प्रतिभागियों को टीएमपी पोर्टल में पंजीयन कराकर प्रमाण पत्र डाउनलोड करवाने का कार्य किया गया।

कार्यक्रम में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदरसिंह पटेल, एनआरएलएम विकासखण्ड समन्वयक अनिता पाटीदार कनिष्ठ यंत्री दिनेश अरजानिया, सहायक यंत्री पीएचई महेश सोलंकी, खण्ड पंचायत अधिकारी, एस आचलिया , सहायक विकास विस्तार अधिकारी रोहित निनामा, पंचायत समन्वय अधिकरी प्रदीप अर्नाल्ड, मनरेगा एपीओ नितिन पाटीदार, स्वच्छ भारत मिशन गमसिंह मेड़ा एवं अन्य समस्त जनपद स्तरीय लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी एव कर्मचारी एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान विभाग के जनपद प्रबन्धक अजित सोलंकी, कंप्यूटर ऑपरेटर पलक गेहलोत एव ग्राम पंचायतों के सचिव रोजगार सहायक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को आभार व्यक्त किया गया। आगे अच्छा कार्य करने हेतु पंचायत उन्नत सूचकांक 2.0 में आवश्यक डेटा एंट्री करने और पंचायतों को ए एवं ए प्लस कैटिगरी में लाने हेतु सभी को प्रेरित किया गया। प्रशिक्षण सह कार्यशाला एवं टीएमपी पोर्टल में समस्त प्रतिभागियों की एंट्री के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया।

मनरेगा उपयंत्रियों के शिष्टमंडल ने विधायक को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा समर्थन पत्र

माही की गूंज, अलीराजपुर।

जिले के मनरेगा अभियंता संघ का शिष्टमंडल अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक निवास, अलीराजपुर (बोरखड़) पर पहुंचा और जोबट विधायक सेना महेश पटेल को ज्ञापन सौंपा।

संघ के पदाधिकारियों ने विधायक को अवगत कराया कि, संविदा उपयंत्री विगत 19 वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, वरिष्ठता के आधार पर पदभार जैसे अधिकार अब तक नहीं मिले हैं। उपयंत्रियों ने यह भी बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2023 को नीति लागू करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु विभागीय स्तर पर लंबे समय तक पालन नहीं हुआ। मई 2025 में नीति लागू होने के बाद भी वेतन विसंगति एवं अन्य समस्याएँ बनी हुई हैं।

शिष्टमंडल ने शिकायत की कि उपयंत्रियों से सीएम हेल्पलाइन, गौशाला प्रबंधन, ई-केवाईसी, आयुष्मान योजना जैसे अतिरिक्त कार्य कराए जा रहे हैं, और लक्ष्यपूर्ति न होने पर वेतन कटौती जैसी अनुचित कार्यवाही भी की जाती है।

विधायक जोबट सेना महेश पटेल ने संघ की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और उन्हें न्यायोचित बताते हुए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नाम समर्थन पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि, वर्षों से सेवा दे रहे संविदा उपयंत्रियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा एवं शासन स्तर पर निरंतर प्रयास करूंगी। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

नवाचार अंतर्गत फोटोकापी सैंटर का शुभारंभ

माही की गूंज, अलीराजपुर।

डीसीसीबी झाबुआ अंतर्गत जिला अलीराजपुर की बी पेक्स बोरखड मे केन्द्र ओर म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अति महत्वपूर्ण ÷सहकार से समृद्धि योजना अंतर्गत÷ अलीराजपुर टाकीज चौराहे पर फोटो कॉपी केंद्र का शुभारम्भ उपायुक्त सहकारिता जिला अलीराजपुर जी.एल. सोलंकी, द्वारा किया गया। इस अवसर पर सोलंकी द्वारा बताया गया कि, आज नवीन 4 समितियों का पुर्नगठन अंतर्गत पंजीयन किया गया अब कुल 40 बी पेक्स पंजीकृत हो गई है।

इस अवसर पर बैंक नोडल अधिकारी राजेश राठौड़, शाखा प्रबंधक जे एस भाभर, अंकेक्षण अधिकारी बी एस चौहान, समिति प्रशासक श्रीमती संगीता चौहान, नवीन वरिष्ठ अंकेक्षक सरपाल सिंह चौहान, अंकेक्षक कैलाश सिसोदिया, संस्था प्रबंधक महेन्द्र सिंह राठौर, सहायक देवेंद्र पाठक, समिति के किसान सदस्य आदि उपस्थित रहे। सभी ने शुभकामना ओर बधाई दी।

'माटी गणेश सिद्ध गणेश' प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार जन अभियान परिषद के तत्वावधान में जिला अलीराजपुर अंतर्गत विकासखंड भाबरा एवं कट्ठीवाड़ा में ÷माटी गणेश सिद्ध गणेश÷ विषय पर विशेष जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

भाबरा के शासकीय हाई स्कूल बड़ा खुटाजा में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों, युवाओं एवं महिलाओं को आगामी गणेशोत्सव में पर्यावरण अनुकूल मिट्टी के गणेश स्थापित करने के महत्व से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण कर्ता ने प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी के गणेश बनाकर कार्यकर्ताओं को निर्माण विधि सिखाई। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मिट्टी के गणेश भी उत्साहपूर्वक बनाए। वक्ताओं ने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस व रासायनिक रंगों से बनी प्रतिमा जलाशयों के लिए हानिकारक होती हैं, जबकि मिट्टी की प्रतिमा शीघ्र ही जल में घुलकर पर्यावरण की सुरक्षा करती हैं।इसी क्रम में कट्ठीवाड़ा आजीविका मिशन कार्यालय में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नवांकुर सखी महिलाओं एवं प्रस्फुटन समितियों की सक्रिय भागीदारी रही। प्रशिक्षक प्रदीप प्रजापति ने उपस्थित जनों को मिट्टी के गणेश प्रत्यक्ष रूप से बनाकर दिखाए तथा तकनीकी जानकारियाँ दीं। इस अवसर पर जिला समन्वयक दीपक जगताप ने कहा कि ÷माटी गणेश सिद्ध गणेश धर्म और आस्था के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं। इससे जल स्रोत भी सुरक्षित रहते हैं और स्वच्छता बनी रहती है।÷

भाबरा विकासखंड के कार्यक्रम में आभार ब्लॉक समन्वयक राम सिंह निगवाल ने व्यक्त किया, वहीं कट्ठीवाड़ा के कार्यक्रम में आभार विकासखंड समन्वयक श्री नगरिया सस्तिया ने माना। उक्त जानकारी जन अभियान द्वारा दी गई।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंति पर कांग्रेस व भाजपा ने किया माल्यार्पण

झाबुआ/अलीराजपुर।

20 अगस्त को जन -जन के प्रिय नेता भारत रत्न,पूर्व एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की 81 जयंति सद्भावना दिवस के रूप में जिला कांग्रेस द्वारा विधायक कार्यालय पर मनाई गई। उक्त जानकारी देते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जंयति पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रांका ने सर्वप्रथम माल्यापर्ण किया तथा स्व.राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने माल्यापर्ण कर स्व. गांधी के बारे में बताया कि, वे युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत थे, वे सबसे युवा प्रधानमंत्री थें उनके द्वारा ही युवाओं को 18 साल में वोट देने का अधिकार मिला तथा कम्प्यूटर /आईटी के जनक थे।

इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने स्व.राजीव गांधी को पुष्पाजंली अर्पित कर कहा कि, उन्हाने राजीव गांधी को करीब से देखा जाना है, उन्होने धैर्य और गरिमा के ससाथ राष्ट्र की सेवा की उन्हाने लाखों भारतीयों में आशा और विश्वास जगाया। भूरिया ने कहा किवे भारत की सस्कृति और सभ्यता से अत्यंत प्रेम करते थे। विज्ञान प्रोद्योगिक, संचार, अवसचंना विकास और अंतिरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में भारत को उंचाई तक पहुंचाया है।

इस अवसर पर महिला नागरिक बैक की संस्थापक अध्यक्ष कल्पना भूरिया, पूर्व जनपद अध्यक्ष मानसिंह मेडा, रूपसिंह डामोर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अकमाल डामोर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लाक अध्यक्ष काना गुण्डिया, सुरेन्द्र गरवाल, कैलाश डामोर रानापुर, समाज प्रकोष्ट अध्यक्ष जितेन्द्र शाह,एनएसयुआई अध्यक्ष नरवेश अमलियार, हर्ष जैन आईटी सेल अध्यक्ष पार्षद शीला मकवाना, जनपद उपाध्यक्ष शीला भूरिया आदिवासी कांग्रेस के खुना भाई, शंकर भूरिया पूर्व अध्यक्ष जनपद, युवक कांग्रेस के हेमेन्द्र बबलू कटारा, नटवर डोडियार, आयुष ओहारी, गोपाल शर्मा, दिलीप भूरिया ढेकलबडी, जोताबेन सहित अनेक महिला कांग्रेस की सदस्य एवं सरपंच पंच सहित अनेक ग्रामीणजन उपस्थित थें। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्वेता गंगा मोहनिया ने माना।

भाजपा विधायक द्वेने माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि

सद्भावना दिवस के अवसर पर जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल जी ने जोबट विधायक निवास पर भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेसजन एवं पदाधिकारियों ने राजीव गांधी के आदर्शों, उनकी दूरदृष्टि और देशहित में किए गए अद्वितीय योगदान को भावपूर्ण स्मरण किया।

विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल ने कहा कि, राजीव गांधी जी ने देश को नई दिशा और नई सोच दी। उनकी नीतियाँ और आदर्श हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणास्त्रोत रहेंगे।

सभी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि वे राजीव गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज में सद्भाव, एकता और प्रगति का संदेश घर-घर तक पहुँचाएँगे। इस अवसर पर जोबट ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सरपंचगण, जनपद सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

जनपद स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित जल जीवन मिशन द्वारा आज दिनांक 19/08/2025 को च. शे.आ.नगर (भाबरा) स्थित जनपद पंचायत सभाकक्ष में अलरीजपुर समूह जल प्रदाय योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आरम्भ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री निधि मिश्रा, तहसीलदार जितेन्द्र तोमर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत इन्दरसिंह पटेल व जनपद अध्यक्ष जगदीश सुरमल गणावा के द्वारा माँ सरस्वती पूजन कर किया गया। कार्यशाला का संचालन रामलखन गुप्ता, सीपी मैनेजर, पीआईयु झाबुआ द्वारा किया गया। इस कार्यशाला मे समूह जल प्रदाय योजना के उददेश्य, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन, प्रशिक्षण व कार्यशैली के बारे में विस्तृत जानकारी समस्त उपस्थित विभागों के अधिकारीयो, प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों को बिन्दुवार दी गई। जहां नल जल योजना का कार्य पूर्ण हो गया है वहाँ पानी केसे पहुंच रहा है उन स्थानों की स्थिति के बारे मे भी बताया गया ये समस्त जानकारी चलचित्रों व स्लाइडों द्वारा सभी के समक्ष प्रस्तुत की गई। कार्यशाला मे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निधि मिश्रा, तहसीलदार जितेन्द्र तोमर के मार्गदर्शन में नल योजना के प्रति उपस्थित अतिथियों को सवेदशील होने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला मे सहयोगी संस्था वसुधा विकास संस्थान एवं पीआईयु झाबुआ के सहयोगी भी उपस्थित रहे। अंत में कार्यशाला में पधारे अतिथीयों का परियोजना प्रबंधक अमित पंत एवं परियोजना समन्वयक गिरीराजसिंह पंवार ने आभार व्यक्त कर समापन किया।

नाबालिग बेटियों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर सजग नहीं है पुलिस, कानून को ताक में रख नहीं करते दर्ज प्रकरण

एसडीएम, एसडीओपी, कलेक्टर और क्षेत्र की विधायक तक महिला, इसके बाद भी नहीं होती सुनवाई

13 साल की गायब बेटी को खोजने की गुहार लगाने पहुंचे माता-पिता को पुलिस ने कहा - बेटी चाहिए कि कागज

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

न्याय व्यवस्था में सभी वर्ग सहित आमजन के लिए और होने वाले अपराधों के लिए अलग-अलग धाराओं में कार्यवाही का प्रावधान है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के लिए शासन ने सख्त कानून बनाए हुए हैं और उससे भी कड़े कानून नाबालिग बच्चों के साथ घटित होने वाले अपराधों के लिए व्यवस्था है। स्थानीय स्तर पर कानून की किताब में लिखे प्रावधानों का पालन करना होता है। आदिवासी अंचल में कानून की अलग किताब चलती है, जो स्थानीय स्तर पर अपनी सुविधा और निजी फायदे के अनुसार चलाई जाती है, जिसमें नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में भी घर के कानून चलाए जाते हैं।

13 वर्षीय नाबालिग लड़की के लिए परेशान माता-पिता

मामला पेटलावद थाना क्षेत्र की सारंगी चौकी के ग्राम मांडन की एक नाबालिग 13 वर्षीय पारुल (बदला हुआ नाम) पिता गोबरिया का है। जुलाई माह के आखिरी सप्ताह में जान-पहचान का व्यक्ति उसे अपने साथ सारंगी में मजदूरी करने ले गया और तब से पारुल घर नहीं लौटी। नाबालिग की खोजबीन के लिए परिवार चार से पांच दिन तक भटकने के बाद तीन अगस्त को सारंगी चौकी में पहुंचकर नाबालिग के गायब होने की लिखित सूचना दी और नाबालिग लड़की को ले जाने वाले संदेही का नाम भी लिखित में दिया गया। नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए सूचना के 24 घंटों में अपराध दर्ज करने का प्रावधान है, लेकिन पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर सारंगी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और लड़की को खोज लाने का आश्वासन दिया। एक रिपोर्ट की रिसीप्ट तक नहीं दी। बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी जब सारंगी पुलिस की ओर से कार्यवाही नहीं की गई, तो पीड़ित परिवार ने बताया कि, 7 अगस्त को एसडीएम (राजस्व) पेटलावद को लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की और 11 अगस्त को पुनः सारंगी चौकी पर आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की। 12 अगस्त को पीड़ित परिवार ने कलेक्टर को जनसुनवाई में शिकायत झाबुआ जाकर की, जहां से सारंगी चौकी पर फोन कर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।

N.C.R.B (एन सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

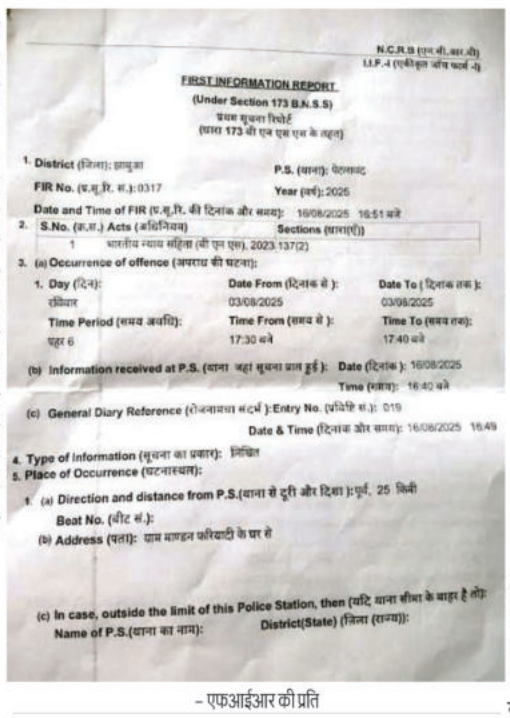

1. District (जिला): झाबुआ P.S. (थाना): पेटलावद
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0317 Year (वर्ष): 2025
Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 16/08/2025 16:51 बजे
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
1 भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 137(2)
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): रविवार Date From (दिनांक से): 03/08/2025 Date To (दिनांक तक): 03/08/2025
Time Period (समय अवधि): पहर 6 Time From (समय से): 17:30 बजे Time To (समय तक): 17:40 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 16/08/2025 Time (समय): 16:40 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 019 Date & Time (दिनांक और समय): 16/08/2025 16:49
4. Type of information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 25 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): ग्राम माण्डन फरियादी के घर से
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो): Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

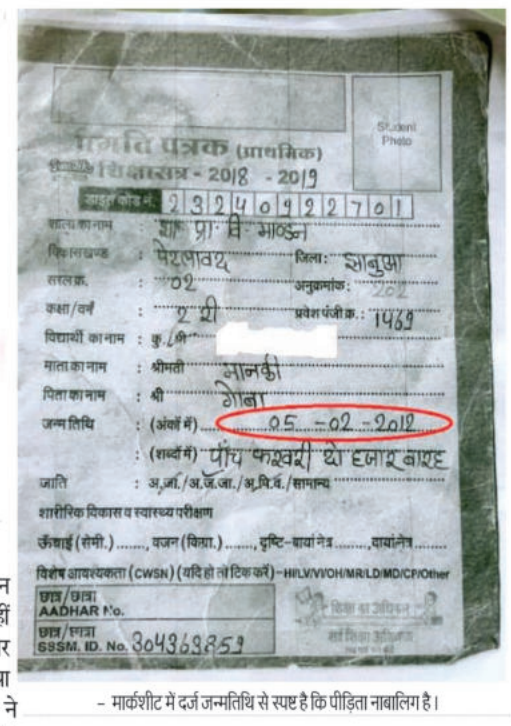

- एफआईआर की प्रति

सी.एम. हेल्पलाइन - शिकायत विवरणी
जन हेतु - जन सेतु
शिकायत क्रमांक : 33775836 दिनांक - 07-08-2025
विभाग का नाम : गृह विभाग
उप-विभाग का नाम : पुलिस
शिकायत कर्ता का नाम : गोबा खराड़ी
पता : मकान नं. 188/1 गली मोहल्ला क्षेत्र माण्डन वार्ड..... ग्राम माण्डन
फ़ोन नंबर : XXXXXXX510, XXXXXXX510
जिला : झाबुआ
क्षेत्र : क्षेत्र अनुभाग : पेटलावद, क्षेत्र थाना : पेटलावद
शिकायत का प्रारूप : प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) न लिखना/ विलंब से लिखना/सही धाराओं में न लिखने संबधी (पुलिस)
शिकायत का विवरण : शिकायतकर्ता गोबा पिता मांगु खराड़ी बताया गया कि थाना सारंगी में आवेदन दिनांक 03.08.2025 को आवेदन किया था आवेदक का नाम गोबा पिता मांगु खराड़ी आवेदक द्वारा बताया गया कि उनकी सम्बंधित थाने में FIR दर्ज नहीं की जा रही है जिससे काफी समस्या हो रही है कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाये
शिकायत की स्थिति : शिकायत निराकरण अधिकारी (एल1) से संपर्क कर शिकायत दे दी गयी है, प्रगति विवरण अपेक्षित है

- जनसुनवाई में की गई शिकायत की प्रति

प्रगति पत्रक (प्राथमिक)
शिक्षासत्र - 2018 - 2019
डाइस कोड नं. 23240922701
शाला का नाम : शा. प्रा. वि. माण्डन
विकासखण्ड : पेटलावद जिला: झाबुआ
सरल क्र. : 02
कक्षा/वर्ग : 2 री प्रवेश पंजी क्र.: 1469
विद्यार्थी का नाम : कु.
माता का नाम : श्रीमती मानकी
पिता का नाम : श्री गोबा
जन्म तिथि : (अंकों में) 05-02-2012
: (शब्दों में) पाँच फरवरी दो हजार बारह
जाति : अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य
शारीरिक विकास व स्वास्थ्य परीक्षण
ऊँचाई (सेमी.) ...., वजन (किग्रा.) ...., दृष्टि-बायां नेत्र ...., दायांनेत्र ....
विशेष आवश्यकता (CWSN) (यदि हो तो टिक करें) - HI/LV/VI/OH/MR/LD/MD/CP/Other
छात्र/छात्रा AADHAR No.
छात्र/छात्रा SSSM. ID. No. 304369853

- मार्कशीट में दर्ज जन्मतिथि से स्पष्ट है कि पीड़िता नाबालिग है।

16 अगस्त को किया मामला दर्ज, पुलिस ने कहा कागज चाहिए कि बेटी

पीड़ित परिवार द्वारा बार-बार अधिकारियों को गुहार लगाने के बाद आखिरकार सारंगी पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग पारुल की गुमशुदगी दर्ज की और शंका के आधार पर दिए गए दो नाम पर मामला दर्ज नहीं किया, बल्कि आरोपी अज्ञात बताकर प्रकरण दर्ज कर लिया। मामला दर्ज होने के बाद जब पीड़ित माता-पिता ने एफआईआर की कॉपी मांगी, तो पुलिस ने लड़की के माता-पिता से साफ कह दिया कि, लड़की चाहिए कि कागज...? विचारणीय प्रश्न उठता है कि, नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले को गंभीरता से लेने की बजाय पुलिस ने पीड़ित परिवार को कई चक्कर लगवाए और नाबालिग के गायब होने के लगभग 20 दिन बाद जिले में हुई शिकायत के बाद मामला दर्ज किया।

संदेही के घर पहुंची पुलिस, मिला था नाबालिग को लौटाने का आश्वासन

नाबालिग के पिता ने बताया कि, रिपोर्ट के बाद परिवार के एक सदस्य को लेकर सारंगी पुलिस संदेही के घर ग्राम सागवा, खवासा चौकी क्षेत्र पहुंची। वहां लड़की तो नहीं मिली, लेकिन संदेही युवक के परिवार वालों ने पांच दिन में लड़की लौटाने की बात कही, लेकिन लड़की नहीं लौटाई। इसके बाद सारंगी पुलिस ने पीड़ित परिवार पर आपसी समझौता करने की बात कहना शुरू कर दिया और आगे कोई कार्यवाही नहीं की। नाबालिग के पिता ने बताया कि, अब मामले में कुछ लोग मेरी मात्र 13 वर्षीय बालिका का विवाह करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि वह अभी मात्र सातवीं कक्षा में पढ़ रही है।

एसडीएम से लेकर कलेक्टर, विधायक महिला, इसके बाद भी नहीं होती सुनवाई

पेटलावद एसडीएम, एसडीओपी पुलिस पेटलावद, कलेक्टर झाबुआ सहित क्षेत्र की विधायक तक एक महिला हैं। ऐसे में महिलाओं, खासकर नाबालिग बेटियों के प्रति हो रहे अपराधों को लेकर सख्ती होनी चाहिए थी, लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। इतने बड़े पदों पर महिला अधिकारियों के होने के बाद भी महिलाओं और नाबालिग बेटियों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर कोई सख्ती नहीं है और पीड़ित परिवार को अपराध तक दर्ज करवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार को अपनी नाबालिग बेटी की जान का खतरा है और पुलिस व प्रशासन से उम्मीद है कि, नाबालिग पारुल को जल्द से जल्द खोजकर परिवार के हवाले किया जाएगा।

आधार पर बवाल जिले में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है

आए दिन हो रहे हंगामें लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नही रेंग रही

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मिल मंसूरी

वैसे तो जिले में कई मुद्दे है जिन पर कभी जिला प्रशासन अपनी नजरे इनायत नहीं करता। फिर चाहे उसमें आमजन के जान-माल का नुकसान कितना ही क्यों ना हो। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो यह लगता है कि, जनहित के मुद्दे भी अब जिला प्रशासन द्वारा नजर अंदाज किए जाने लगे है। ऐसा नहीं है कि, इन मुद्दों पर जिला प्रशानसन का ध्यान आकर्षण नहीं करवाया गया हो। जनआक्रोष और अखबारों की सुर्खियां यह बताती है कि, जनहित के मुद्दों पर हमेशा आवाज उठती है लेकिन इससे जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। चाहे फिर वह भ्रष्टचार का मामला हो या फिर माफियाओं से जुड़ा मामला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब अधिकारियों की जान पर बन आती है तो ताबड़तोड़ कार्रवाईयां होने लगती है। छापे पड़ जाते है और संपत्तियां सील हो जाती है। इसके विपरीत जिले के आम नागरिकों की स्थिति बिल्कुल उलट है। आमजन वर्षों किसी काम के लिए चप्पलें घिस लें लेकिन मजाल है कि, अधिकारी थोड़ा भी तरस या रहम खाए। इस समय जिले में प्रशासन की तूती बोल रही है। अगर प्रशासन रात को दिन कह दे तो वह दिन हो जाता है और दिन को रात कह दे तो रात हो जाती है। मतलब सीधा सा है अगर प्रशासन चाहे तो गलत को सही और सही को गलत बना दे। जिला प्रशासन के इस करतब में अगर कोई टांग अड़ाएगा तो समझो वह किसी काम का नहीं रहेगा। वैसे भी जिला प्रशासन में द्वेष भावना तो कूट-कूट कर भरी हुई है। इसके कई प्रमाण मौजूद है। अगर आपने प्रशासन की मंशा के अनुरूप कोई काम नहीं किया तो समझ लीजिए कि, आप बड़ी आसानी से प्रशासन के टारगेट पर आ जाएंगे।

कुछ ऐसी ही स्थिति इन दिनों जिले में आधार कार्ड सेंटरों पर चल रहै फर्जीवाडे को लेकर बनी हुई है। आधार कार्ड सेंटरों और लोकसेवा केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने या अपडेशन के लिए अवैध वसूली जोरों पर है। जिले के ग्रामीणों से आधार संबंधी कार्यों के लिए जबरन भारीभरकम रकम की वसूली हो रही है। मगर इस गंभीर स्थिति को जिला प्रशासन आंख मूंद कर वैध वसूली करार दे रहा है। माही की गूंज पिछ्ले कई महीनों से आधार सेंटरों पर हो रही धांधलियों को उजागर करता आ रहा है। जिसमें यह मामला निकलकर सामने आया था कि, आधार कार्ड के इस अंधे कुंए में ठेकेदार करोड़ों के वारे-न्यारे कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आधार सेंटरों के ठेकेदारों की अवैध वसूली, दादागिरी और मनमानी मय प्रमाण के माही की गूंज छाप चुका है। प्रशासनिक जांचों में यह साफ भी हो चुका है कि आधार कार्ड सेंटरों पर गड़बड़ियां हो रही हैं। बावजूद इसके आधार कार्ड सेंटरों के संचालक या ठेकेदार पर कोई कार्रवाई ना होना जिला प्रशासन व उसके आला अधिकारियों पर कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहै है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर आधार सेंटरों पर बैठे संचालक और ठेकेदार अपनी पहुंच का रूबाब झाड़ते दिखाई देते है। हम पिछ्ले अंकों में ठेकेदार के वह बोल भी प्रकाशित कर चुके है जिसमें वह सीधे कलेक्टर से बात होने का हवाला संचालक देता रहा है। ठेकेदार की इस बकलोल को सच मान लिया जाए तो यह सीधे तौर पर कलेक्टर को इस मामले से जोड़ रहा है। जब माही की गूंज ने आधार कार्ड सेंटरों के ठेकेदार के खिलाफ भांडा फोड़ अभियान चलाया तो ठेकेदार ने झल्लाते हुए इसकी पुष्टी भी कर दी कि, खेल में बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल है। नतीजा यह निकल कर सामने आया कि, आधार कार्ड सेंटरों पर कार्रवाई होने के बजाय माही की गूंज के प्रतिनिधि व प्रधान संपादक पर ही एफआईआर दर्ज हो गई।

अब वर्तमान में फिर से आधार कार्ड सेंटर का मामला गर्माता नजर आ रहा है। हुआ कुछ यूं कि, माही की गूंज में आधार कार्ड सेंटरों की हकीकत प्रकाशित होने के बाद कुछ राजनीति दलों के नेता इस समस्या को लेकर जमीनी स्तर पर निकल पड़े। ओर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं जानी और प्रशासन से आधार कार्ड सेंटर बढ़ाने की मांग भी की गई। इसी तारतम्य में शनिवार को जिले के कल्याणपुरा कस्बे में आधार कार्ड सेंटर पर अवैध वसूली को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। कल्याणपुरा के आधार कार्ड सेंटर पर पहुंचे राजनीतिक दल के एक नेता को शिकायत मिली कि, यहां पर आधार कार्ड बनाने को लेकर अवैध वसूली की जा रही है। नेता जी ने जब आधार कार्ड सेंटर के संचालक से बात कर इस पर आपत्ती दर्ज करना चाही तो बकोल नेता जी लोगों ने हमें पैसे वसूली की बात बताई, हमने कहा या तो रूपए देते हुए वीडियो बना लो या ऑन लाइन भुगतान कर दो। लोगों ने ऑन लाइन भुगतान कर दिया। हमने इसका विरोध दर्ज कराया। इसके बाद कुछ लोग यहां पहुंचे और हमें एक कमरे में बंद कर दिया। मारपीट भी की। हमारे एक साथी ने बाहर से फोन कर पुलिस को बुलाया और हमें बाहर निकाला। इसके बाद हम कल्याणपुरा थाने पर एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जिसके बाद रविवार को मामले ने और तूल पकड़ लिया। जिले भर से राजनीतिक पार्टी व आदिवासी संगठनों के लोग जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हो गए। इन्होने आजाक थाने पर पहुंच कर ज्ञापन दिया और प्रदर्शन किया। एसपी कार्यालय पहुंचकर भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इस दौरान आजाक थाने पर कार्यकर्ताओं और डीएसपी के बीच तीखी बहस भी हुई। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आदिवासियों की सुनवाई नहीं करने का आरेप भी लगाया।

इसके विपरीत आधार कार्ड सेंटर के संचालक ने भी व्यापारियों को इक्खट्टा किया और नेता जी पर अवैध वसूली का आराप लगाते हुए नेता जी पर ही मारपीट का आरोप लगाया। आधार कार्ड सेंटर के संचालक के अनुसार उन्हे परिचित लोगों ने बीच बचाव कर बचाया।

सोमवार को इस मुद्दे पर कल्याणपुरा के व्यापारियों ने मिलकर झाबुआ एसपी के नाम कल्याणपुरा थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि, आए दिन ये लोग हम व्यापारियों को परेशानन करते है। जब इनका कार्य नहीं होता तो यह लोग समाज को बांटने के लिए जातिवाद का मुद्दा लाकर लोगों को भड़काते है। इससे जिले का माहौल बिगड़ता है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इस पर अंकुश लगाया जाए।

हम यहां किसी का पक्ष नही ले रहे है, ना ही किसी का विरोध कर रहे है। लेकिन जिले में आधार कार्ड सेंटरों की जो स्थिति नजर आ रही है वह बहुत कुछ बयां कर रही है। हो सकता है कि, नेता और आदिवासी संगठनो द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे है वह सही हो, क्योंकि माही की गूंज इस पर विस्तृत खबरें प्रकाशित्त कर चुका है। मगर ऐसा भी हो सकता है कि, आधार कार्ड सेंटर संचालक ने जो आरोप यहा नेताजी पर लगाए है वह भी सच हो। यह सब जांच का विषय है। लेकिन आधार कार्ड सेंटरों के मामले में जिला प्रशासन के रवैये शुरू से ही संचालकों को संरक्षण देने वाला दिखाई दिया है। क्योंकि जब भी आधार कार्ड सेंटरों पर सवाल खड़े किए जाते है, आवाज उठाने वालों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई देखने को मिलती है। जिसका माही की गूंज खुद एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए अगर नेता जी सही है तो यह पक्का है कि, उनके सर पर भी प्रशासनिक कार्रवाई की तलवार जरूर लटकेगी। जैसा कि पूर्ववत होता आया है।

खैर जो भी हो लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि, पुलिस अपनी जांच इस मामले में कब तक पूरी करती है और किस नतीजे पर पहुंचती है। यह भी दिलचस्प होगा कि, नेताजी पर कार्रवाई होती है या फिर आधार कार्ड सेंटर के संचालक इस बार लपेटे में आएंगे। हालांकि इस बात में संशय है क्योंकि आधार कार्ड सेंटरों के संचालक और ठेकेदार सीधे तौर पर जिलाधिकारियों के संपर्क में रहते है। तो होगा वही जो आधार कार्ड सेंटरों के ठेकेदार की मर्जी होगी। क्योंकि ठेकेदार हो ना हो इस बार भी कलेक्टर से बात तो जरूर करेगा। हो सकता है कि, बात हो भी गई हो और ठेकेदार ने अपने अधिनस्त संचालकों को यह बता दिया हो कि कलेक्टर मेडम से बात हो गई है।

महाकाल मंदिर के दान पेटी ने उगला खजाना

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर सावन मास में भक्तों के लिए संभवतः सर्वाधिक प्रिय रहा। यही वजह है कि इस पवित्र माह में देशभर से 85 लाख दर्शनार्थी बाबा के दर पर आए और मंदिर को दान के साथ ही लड्डू प्रसाद बिक्री और वीआईपी टिकट से 27 करोड़ की आय हो गई।

दरअसल, सावन का महीना शिव आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इसलिए इस महीने में देश के सभी ज्योतिर्लिंगों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण माने जाने के कारण सावन के महीने में 11 जुलाई से 9 अगस्त तक यहां 85 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान, भक्तों ने यहां खुले दिल से दान देने के साथ ही वीआईपी टिकट और लड्डू भोग प्रसाद खरीदने में भी कंजूसी नहीं बरती। नतीजतन दान पेटी खोलने पर उसमें पांच करोड़ की राशि निकली। वहीं, अन्य स्त्रोतों से मंदिर को 22 करोड़ की आय हुई।

ऐसे हुई मंदिर को 27 करोड़ की आय

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि, श्रावण माह भगवान शिव को अति प्रिय है। इसलिए सावन के 30 दिनों में देश-विदेश से 85 लाख श्रद्धालुओं ने आकर बाबा के दर्शन किए। इसमें नागपंचमी पर आए भक्त भी शामिल हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने दान पेटी, ऑनलाइन चेक और नकद के माध्यम से करीब 5 करोड़ का दान किया। वहीं, लड्डू प्रसादी, शीघ्र दर्शन सहित अन्य स्त्रोत से भी 22 करोड़ की आय हुई. इस तरह मंदिर को कुल 27 करोड़ रुपए की आय हुई है।

महाकाल लोक से भी आय में हुई वृद्धि

महाकाल मंदिर के मुताबिक महाकाल लोक बनने के बाद से दर्शनार्थियों की संख्या में जमकर इजाफा हुआ। 2023 में 5.28 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 2024 में यह संख्या 7.32 करोड़ हो गई। पिछ्ले दो साल में करीब 12 करोड़ 32 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं। श्रद्धालु के दान से मंदिर की व्यवस्था, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, गोशाला, महाकालेश्वर वैदिक शोध संस्था,पर्वों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाकाल मंदिर विस्तारीकरण और मंदिर की सुरक्षा पर पैसा खर्च होता है।

साल दर साल ऐसे बढ़ती गई दान की राशि

साल	दान (रुपये करोड़ में)
2019-20	15,04,68,572
2020-21	9,46,04,472
2021-22	19,97,42,018
2022-23	38,91,54,901
2023-24	59,91,20,297
2024-25	51,22,39,268

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422